सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 311, नई दिल्ली । रविवार, 19 जनवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 सभी किराएदारों को बिजली-पानी पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा....
06 परीक्षा के दिनों में इन बातों का ध्यान रखिए
08 सिंगापुर के राष्ट्रपति ने पट्टचित्रा गांव पुरी की हरिराजपुर का दौरा किया

दिल्ली में सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों पर लगा प्रतिबंध, फ्लाइट्स के लिए तय किए गए नियम

संजय बाटला

गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों के तहत कई नियम लागू किए हैं। पैराग्लाइडर पैरामोटर हैंग ग्लाइडर मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) सहित सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों की उड़ान पर 18 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

15 दिनों के लिए लागू रहेंगे प्रतिबंध, पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम को लेकर कई नियम लागू किए हैं। ये आदेश 18 जनवरी से लागू हो गए हैं 15 दिनों यानी एक फरवरी तक लागू रहेंगे। इनका पालन नहीं करने पर लोगों को कई तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।

इस पूरे समय के दौरान दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) सहित सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आम जनता की सुरक्षा के लिए हो सकता है खतरा पैदा

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के मुताबिक, भारत के दुश्मन, कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स जैसे हवाई साधनों के उपयोग से आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

करना पड़ सकता है कानूनी कार्रवाई का सामना

इनमें हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रो-लाइट विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान, क्वाडकाप्टर या यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग आदि भी शामिल हो सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सभी तरह के उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर रोक लगा दी है। इनका पालन नहीं करने पर लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

डायल ने जारी की एडवाइजरी

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) द्वारा यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। आइजीआई एयरपोर्ट पर आज यानि 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक रोजाना दो घंटे से अधिक समय के लिए विमानों के उड़ान और प्रस्थान पर पाबंदी रहेगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों और कर्तव्यपथ पर होने वाले कार्यक्रम के चलते यह फैसला लिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय के रोजाना करीबन 1,300 विमानों का आवागमन

यात्री इन दिनों एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस से विमान के उड़ान का समय पता कर के ही जाएं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आइजीआइए) पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय के रोजाना करीबन 1,300 विमानों का आवागमन है, जिसमें दो लाख से अधिक लोग रोजाना यात्रा करते हैं।

डायल ने शनिवार को अपने एक्स पर पोस्ट कर एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि नोटम के अनुसार गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक सुबह 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे के बीच एयरपोर्ट से विमानों का उड़ान और प्रस्थान नहीं होगा।

एआईएमटीसी के बैनर तले 24 जनवरी को ड्राइवर्स डे की घोषणा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। परिवहन संघों की शीर्ष संस्था एआईएमटीसी (ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस) के बैनर तले सभी परिवहन संघ और संघ देश से हर साल 24 जनवरी को ड्राइवर्स डे मनाने का आह्वान करते हैं। एआईएमटीसी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरीश सबरवाल ने कहा कि इस बार एआईएमटीसी द्वारा 24 जनवरी 2025 को ड्राइवरों के सम्मान और धन्यवाद के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। हरीश सबरवाल ने समाज से ड्राइवरों को धन्यवाद कहने, फूल देने, शुभकामनाएं देने या किसी भी सम्मानजनक तरीके से अभिवादन करने का आग्रह किया। आज एएसआरटीयू (एसोसिएशन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग) मुख्यालय द्वारका में हुई बैठक के बाद यह आह्वान किया गया। बैठक में एआईटीडी (एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट) के निदेशक श्री बीएन पुरी, एएसआरटीयू के कार्यकारी निदेशक श्री सूर्यकिरण, एआईएमटीसी के हरीश सबरवाल और नवीन गुप्ता और असम सरकार के सलाहकार अनिल छिकारा मौजूद थे।

नोएडा में ये चार दिन रहेगा डायवर्जन, एडवाइजरी जारी घर से निकलने से पहले देखें रूट; नहीं तो होगी भारी परेशानी

गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल और परेड के मद्देनजर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जिले में रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। 22 जनवरी से 26 जनवरी तक होने वाले डायवर्जन की जानकारी यहां देखें। साथ ही वैकल्पिक मार्गों की भी जानकारी दी गई है। घर से निकलने से पहले देखें कौन सा रास्ता खुला और कौन सा बंद रहेगा।

नोएडा। यातायात पुलिस ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस परेड रिहर्सल व गणतंत्र दिवस परेड को लेकर जिले में रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। लोगों से 22 जनवरी से 26 जनवरी कार्यक्रम समाप्ति तक समय-समय पर होने वाले डायवर्जन प्लान का पालन करने की अपील की है।

डीसीपी यातायात लाखन सिंह यादव ने बताया कि 22 जनवरी रात 10 बजे से 23 जनवरी तक कार्यक्रम समाप्ति तक व 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी को कार्यक्रम समाप्ति तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। गौतमबुद्ध नगर से दिल्ली राज्य में प्रवेश कर गंतव्य तक जाने वाले मालवाहक (भारी, मध्यम व हल्के) वाहनों का सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली राज्य में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

आपातकालीन वाहनों को मिलेगी छूट

डायवर्जन के अलावा परिस्थितियों को देख अन्य वाहनों का डायवर्जन (Traffic Diversion) भी हो सकता है। डायवर्जन के वक्त आपातकालीन वाहनों को सकुशल गंतव्य को भेजा जाएगा। वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।

ये है डायवर्जन प्लान

चिल्ला रेड लाइट (बॉर्डर) से दिल्ली राज्य में प्रवेश कर गंतव्य जाने वाले वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर जा सकेंगे।

डीएनडी (बॉर्डर) से दिल्ली राज्य में प्रवेश कर गंतव्य जाने वाले वाहन डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर जा सकेंगे।

कालिंदी कुंज यमुना (बार्डर) से दिल्ली राज्य में प्रवेश कर गंतव्य जाने वाले वाहन यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहा से डायवर्ट होंगे, जो नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर दिल्ली राज्य में प्रवेश कर अन्यत्र जाने वाले वाहन फलैदा कट, रबुपुरा से सर्विस रोड होकर, गलगोटिया, गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी से होते हुए पुस्ता तिराहे से होंडा सीएल चौक से कस्बा कासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर दिल्ली राज्य में प्रवेश कर गंतव्य को जाने वाले वाहन जीरो प्वाइंट से परीचौक की ओर डायवर्ट होंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अब इनके लिए जरूरी होगी ड्राइविंग ट्रेनिंग

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार ने वाहन चालकों के समुचित प्रशिक्षण पर जोर देते हुए नए बनने वाले ड्राइविंग सेंटरों के लिए 250 जिलों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है। इन सभी में अगले दो साल के भीतर सेंटरों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इन केंद्रों से एक वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण पाने वाले लोगों की संख्या का अनुमान भी प्रस्तुत किया है।

> उत्तर प्रदेश प्राथमिकता वाले राज्यों में ड्राइविंग सेंटरों के लिए उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में उत्तर प्रदेश से लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर, आगरा, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी और आजमगढ़ का चयन किया गया है।

नई दिल्ली। वाहन चालकों के समुचित प्रशिक्षण पर जोर दे रही केंद्र सरकार ने नए बनने वाले ड्राइविंग सेंटरों के लिए 250 जिलों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है। इन सभी में अगले दो साल के भीतर सेंटरों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सबसे अधिक 25 जिले कर्नाटक के चुने गए हैं, जबकि तमिलनाडु के 21 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे। ये दोनों राज्य सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में शीर्ष पांच में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 16 और बिहार तथा बंगाल में 15-15 ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे।

हर केंद्र से एक साल में दो हजार नए लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग

पहली बार केंद्र सरकार ने इन केंद्रों से एक वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण पाने वाले लोगों की संख्या का अनुमान भी प्रस्तुत किया है। हर केंद्र से एक साल में दो हजार नए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 20 हजार लोग (दोपिहया वाहन चालक समेत) अपने डीएल के नवीनीकरण आदि के लिए रिफ्रेशर कोर्स कर सकेंगे। जिन लोगों के पास ड्राइविंग सेंटरों से पास होने का प्रमाणपत्र होगा, उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में डीएल बनवाने के लिए कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा केंद्र और राज्यों में सरकारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए इन केंद्रों से प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र लेना भी अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। ऐसे ड्राइवरों की संख्या 10 लाख है।

उप्र प्राथमिकता वाले राज्यों में

ड्राइविंग सेंटरों के लिए उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में उत्तर प्रदेश से लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर, आगरा, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी और आजमगढ़ का चयन किया गया है।

बिहार, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बंगाल के जिलों में पहले चरण में ही ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि आइटीआइ सिमुलेटर और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का बंदोबस्त कर लें तो वे चालकों को प्रशिक्षण दे सकते हैं।

वहीं पर दूसरी ओर नोएडा यातायात पुलिस (Noida Traffic Diversion) ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस परेड रिहर्सल और गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए जिले में रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। जिसके तहत लोगों से अपील की गई कि वह सभी 22 जनवरी से 26 जनवरी तक के कार्यक्रम को देखते हुए वाहन चालक समय-समय पर होने वाले डायवर्जन प्लान का पालन करें।

धड़ल्ले से चल रहे हैं नकली चेसिस नंबर के वाहन, परिवहन विभाग ने चलाया विशेष अभियान, 13 एफआईआर दर्ज

परिवहन विशेष न्यूज

रजिस्ट्रेशन की कम दरों का लाभ उठाने के लिए चल रही नकली चेसिस नंबर वाली गाड़ियों के खिलाफ जिला परिवहन एवं सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है। विभाग का कहना है कि नकली चेसिस नंबर वाले वाहन न केवल अवैध हैं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हैं।

जयपुर। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार नकली चेसिस नंबर वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह समस्या विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सामने आई है, जहां वाहन मालिक राजस्थान से खरीदे गए वाहनों को अन्य राज्यों में पंजीकृत करवा रहे हैं। इन राज्यों में कम कर दरों का लाभ उठाने और जांच से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

जांच के दौरान पाया गया कि कई वाहनों के चेसिस नंबर नकली थे, जो निर्माताओं द्वारा जारी नहीं किए गए थे। यह गंभीर मामला जयपुर से दिल्ली के बीच चल रही यात्री बसों में सामने आया। विभाग ने इन गाड़ियों के नकली पहचान संख्या (वीआईएन) की पुष्टि की और विशेष टीमें बनाकर वाहनों को जब्त किया।

परिवहन निरीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें वाहन मालिकों और कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर (द्वितीय), संजय शर्मा ने बताया कि यह अभियान पिछले दो वर्षों से निरंतर चल रहा है और अब तक कई संदिग्ध वाहनों को जब्त किया जा चुका है। यह अभियान न केवल नकली चेसिस नंबर वाले वाहनों को रोकने का प्रयास है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपने वाहनों की पूरी जानकारी और वैध दस्तावेज रखें। नकली चेसिस नंबर वाले वाहन न केवल अवैध हैं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हैं। विभाग इस अभियान को आगे भी जारी रखेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

एड़ी में दर्द की शिकायत तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, इससे बचने का क्या उपाय है?

आजकल लोगों में एड़ी में दर्द की शिकायत बहुत देखी जा रही है। इस समस्या के बढ़ने के कई कारण हैं जैसे

1. अक्सर महिलाओं के एड़ियो में ज़्यादा दर्द होता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो अक्सर गलत जूते-चप्पलों का चुनाव कर लेती हैं और इन्हे पहन कर चलने से एड़ी में दर्द होने लगता है।

2. अगर आपके एड़ी में पहले कभी चोट लगी है तो मौसम बदलने के साथ ही ये दर्द फिर से पनपने लगता है। और फिर दर्द बढ़ जाता है। अगर इस रोग पर ध्यान ना दिया जाए तो ये चोट घाव में भी तब्दिल हो सकता है।

3. एड़ियों में दर्द का एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो है मोच। पूराने मोच भी दर्द में तब्दिल हो जाते हैं। इसके अलावा गठिया के कारण भी दर्द की शिकायत हो सकती है।

4. शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी एड़ियों में दर्द होने लगता है।

इन घरेलू उपचारों की मदद से आप एड़ी के दर्द से आराम पा सकते हैं

1. अगर आपके एड़ी में ज़्यादा दर्द है तो सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं ये किसी भी दर्द के लिए बहुत पायदेमंद है।

2. ऐड़ी में दर्द हो तो कुछ दिनों तक हील को नज़रअंदाज़ करें। क्योंकि हील पहनने से एड़ी दर्द की समस्या और बढ़ सकती है।

3. आधे बाल्टी गर्म पानी में पैरों को डालकर थोड़ी देर बैठें। इससे सूजन और दर्द खत्म होता है।

4. एड़ियों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक सूती कपड़े में बर्फ के कुछ टुकड़े डालकर दिन में 4 से 5 बार एड़ी को सेंके।

एडी के दर्द का रामबाण इलाज एडी का दर्द अति कष्टकारी होता है, अक्सर ये दर्द महिलाओ को अधिक होता है। सारा दिन खड़ा रहना या ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना या हड्डी का बढ़ना इसके मुख्य कारण हैं।ऐसे में ये रामबाण उपचार सौ फीसदी असरकारक हो सकता है। जाने.

आवश्यक सामग्री

1. नौशादर =एक चौथाई छोटा चम्मच

2. ग्वार पाठा (एलो वेरा)=आधा चम्मच

3. हल्दी=आधा चम्मच

बनाने और लगाने की विधि नौशादर एक पीस (एक चौथाई छोटा चम्मच), गवार पाठा – आधा चम्मच, और आधा चम्मच हल्दी। एक बर्तन में गवार पाठा धीमी आंच पर गरम करे, उस में नौशादर और हल्दी डाले, जब गवार पाठा पानी छोड़ने लगे तब उसे एक कॉटन के टुकड़े पर रख ले और थोड़ा ठंडा करे। जितना गरम सह सके, उसे एक कपडे पर रख कर एड़ी पर पट्टी की तरह बांध लीजिये, ये प्रयोग सोते समय करे क्योंकि इसे बाँध कर चलना नहीं है। ये प्रयोग कम से कम 30 दिन तक पुरे धैर्य से करे। ये प्रयोग बिलकुल सरल और सर्वश्रेष्ठ है, एड़ी के दर्द वाले व्यक्ति को इसे ज़रूर आज़ माना चाहिए। जल्दी आराम के लिए आप साथ में एलो वेरा की सब्जी या घर पर बना हुआ जूस भी पी सकते हैं।

सर्दी-जुकाम होगा छूमंतर, बस इन 5 घरेलू उपायों को अजमाएं, मिलेगा आराम

सर्दियों में कमजोर इम्यूनिटी के कारण सर्दी-जुकाम होना आम है। ठंडी हवाओं के चपेट में आ जाने सर्दी-खांसी जैसी बीमारियां होने लगती है। इस मौसम में हर कोई इन समस्याओं से परेशान रहता है जैसे कि नाक बहना, गले में खराश और खांसी आदि। किचन में मौजूद इन घरेलू नुस्खों के जरिए सर्दी-खांसी ठीक हो जाएगी।

सर्दियों के दौरान सर्दी-जुकाम का होना आम बात है। इस मौसम में खुद का ध्यान न रखें, तो सर्दी के कारण बीमारियां होने लगती है। ज्यादातर लोगों की इम्यूमिटी कमजोर रहती है, जिस वजह से सर्दी-जुकाम की समस्या बनीं रहती है। सर्दी के मौसम में गले में खराश, नाक बहना और खांसी जैसी समस्याएं सबसे कॉमन होती है लेकिन इससे निजात पाने में कई हफ्ते तक लग जाते हैं। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो आपके किचन में मौजूद इन जड़ी-बूटियों व मसालों का प्रयोग कर सकते हैं। आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आपको काफी आराम मिलेगा। अगर आप भी ठंड में जुकाम और खांसी से परेशान हैं, तो ये 5 घरेलू नुस्खों को जरुर इस्तेमाल करें।

अदरक और शहद का इस्तेमाल करें

सर्दियों में अगर आप सर्दी-जुकाम से परेशान हैं, तो आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एंटी-इफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। सर्दी-जुकाम से राहत पाने के लि आप एक चम्मच अदरक का रस और शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार सेवन करें। ऐसा करने से आपकी खांसी, गले की खराश और नाक बंद जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।

स्टीम लेना

अगर आपकी ठंड लग गई है और नाक बंद है, जिस कारण से सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, तो आप भाप जरुर लें। आप गर्म पानी के सामने चेहरे को पास रखकर भाप ले सकते हैं। इसमें आप ऐंसिशियल ऑयल या फिर विक्स डालकर भाप ले सकते हैं। इससे आपको काफी आराम मिलेगा।

हल्दी वाला दूध

गौरतलब है कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो सर्दी-जुकाम को दूर करते हैं। एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीने से गले में काफी राहत मिलती है और सर्दी जल्दी ठीक होती है।

तुलसी और अदरक का काढ़ा

सर्दियों में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तुसली और अदरक का काढ़ा काफी फायदेमंद रहता है। तुलसी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण अधिक होते हैं। सर्दी-जुकाम के दौरान तुलसी के पत्तों और अदरक का काढ़ा बनाकर पीने से शरीर में गरमी बनीं रहती है और जुकाम में आराम मिलता है।

नमक के गरारे करें

सर्दियों के दौरान कई लोगों का गला खराब रहता है। ऐसे में अपने गले की सूजन को कम करने के लिए नमक का गरारा बेहद प्रभावी है। आप एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर गरारे करें। इससे आपके गले में काफी राहत मिलेगी।

चना सबसे पौष्टिक

आजकल सभी पौष्टिक आहार की जगह ब्रेड पकोड़ा वड़ा_पाव (सड़ा पाव) भी ब्रेड पकोड़ा के परिवार का सदस्य है, समोसा(मैदे से बना), चाउमीन, मंचूरियन और न जाने क्या क्या खाते रहते हैं?

ब्रेड में लिपटे वो सारे सामान जैसेः- पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, ब्रेड आदि बहुत ही खतरनाक हैं। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया ही घातक है, पहले मैदे को सड़ाया जाता है फिर हाई फ्लेम पर पकाया जाता है। बाजार में मिलने वाले ज्यादा खाने वाले आहार खुले हो या पैकेट बंद सामानों में पाम ऑयल, मैदे अजीनों मोटो का उपयोग किया जाता है।

कुछ ब्रांडेड कम्पनी वाले अपने नमकीन वेफर्स में पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो आगे चल के आपके घुटने खराब करेगा और साथ ही हार्ट अटैक का मरीज भी बनाएगा।

जब की चना मसल्स और पावर बढ़ाने का सबसे बेहतरीन आहार है। कई लोग बोलते हैं चना अच्छा नहीं लगता, बच्चे खाते नहीं हैं। आपको बता दें चने को खाने के चार पांच तरीके हैं। आपको तरीके जरूर पसंद आएंगे, जाने

1. चने को रात में भिगो दें और सुबह चबा कर खा लें

2. चने के साथ में थोड़ी मूंग, थोड़ी किसमिस, थोड़े कच्चे सींगदाने और दो चार बादाम भीगो दे और सुबह खा लें

3. **भूंजे चने** आजकल तो पैकेट बंद भुजें चने आने लगे हैं पर वो देशी नही रहते ऑस्ट्रेलियन हैं जो फायदा कम करते हैं। इसलिए देशी चने लेकर खुद भुजवा लें और सर्दियों में गुड़ के साथ खाएं और गर्मियों में थोड़ा प्याज़ एक दो मिर्ची, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सरसों तेल डालकर मिला लें फिर खाएं

4. **चने का सत्तू** शहर के लोग चने का सत्तू क्या होता है शायद नहीं जानते होंगे पर उम्मीद करता हूं गांव वालों को जरूर पता होगा।

सत्तू बनाने की विधि पहले चने धो ले, फिर भुनवा ले और फिर छिलके निकालने हो तो निकालिए नही निकालना हो मत निकालिए और फिर उसे हाथ चक्की में पीस लीजिए बन गया बेस्ट क्वालिटी का सत्तू इसे आप नमक या गुड़ के साथ खूब पेट भर के खाइए, यहां एक बात बता दूं बाजार में जो बच्चों के लिए हेल्थ टॉनिक मिलते हैं जैसे हॉर्लिक्स, बोर्नबिटा, बूस्ट वह सब भी चने के सत्तू और जौ के सत्तू से ही बनते हैं (आप जाकर चेक कर सकते हैं) जिसे आप घर पर 60-70 रुपए किलो में तैयार कर लेंगे और वहीं चीज आपको विदेशी कंपनियां 600 से लेकर 800 रुपए किलो बेचती हैं।

5. चने की सब्जी बनाकर रात में देशी चने लीजिए 100 ग्राम धुलकर भिगो दीजिए, सुबह अच्छी तरह भीग गए होंगे, उसे किसी तांबे या स्टील में बर्तन में हल्की आंच पर उबलने को रख दीजिए उतने समय में आप दो प्याज, एक टमाटर और एक दो हरी मिर्ची काट लीजिए। जब चने उबल जाएं, थोड़ा सा तेल कड़ाही में डालिए तेल गर्म होने पर जीरा फिर कटा प्याज मिर्ची छोड़ दीजिए एक मिनट बाद टमाटर डाल और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दीजिए जब प्याज हल्का भूरा हो जाए तो चने का पानी छानकर चने डाल दीजिए थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कीजिए, बस आपके स्वादिष्ट चने तैयार है, थोड़ी धनिया पत्ती

और थोड़ा नींबू का रस डालकर जिसे भी देंगे कोई मना नही कर पायेगा,, आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं।

अच्छा खाइए स्वस्थ्य रहिए।

चक्कर आने पर घरेलू उपचार

(1) अचानक सिर का घूमना,

(2) आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाना,

(3) कुछ नजर नहीं आना,

(4) सारी धरती घूमती सी नजर आना.

इन सबको ही चक्कर आना कहते हैं।

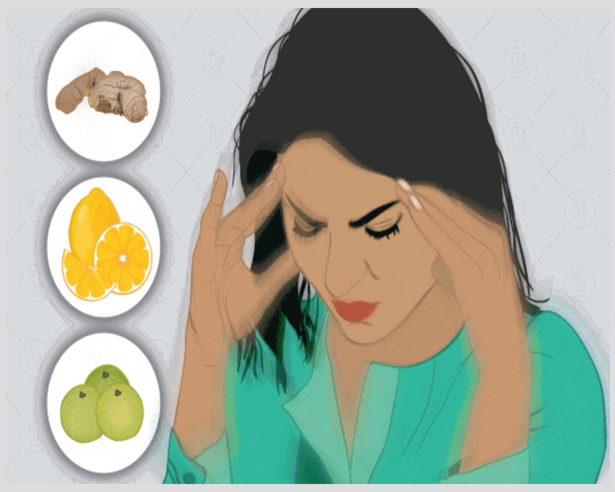

चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं चक्कर आने पर किये जाने वाले घरेलू उपचारों के बारे में।

चक्कर आने के घरेलू उपचार के बारे में जानकारी से पहले यह जान ले की चक्कर आना किसे कहते है।

किसी को चक्कर आते हैं, थोड़ी देर तक बैठे रहने के बाद जैसे ही उठते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसा लगता होगा कि चारो ओर की चीजें तेजी से घूम रही हैं। यह तब होता है, जब मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति कम हो जाती है। रक्तचाप में अचानक कमी से भी यह स्थिति पैदा हो सकती है। घर में रखी चीजों द्वारा हम इस का उपचार कर सकते है।

जानिये इन उपायों के बारें में

1. लौकी को पकाए और पकने के बाद सूखी हुई लौकी को डण्ठल की तरफ से काट दें, ताकि अन्दर का खोखलापन दिखाई दे। अगर सूखा गूदा हो तो उसे निकाल दें। अब इसमें ऊपर तक पानी भर कर 12 घण्टे तक रखें फिर हिलाकर पानी निकाल कर साफ कपड़े छान लें। इस पानी को ऐसे बर्तन में भरें, जिसमें आप अपनी नाक डुबो सकें। नाक डुबोकर जोर से सांस खींचें, ताकि पानी नाक से अन्दर चढ़ जाए। पानी खींचने के बाद नाक नीची करके आराम करें। इस उपाय से चक्कर आने की समस्या सदा के लिए खत्म हो जाती है।

चक्कर आने पर तुलसी के रस में चीनी मिलाकर सेवन करने से या तुलसी के पत्तों में शहद मिलाकर चाटने से चक्कर आना बंद हो जाता है।

चक्कर आने पर धनिया पाउडर 10 ग्राम तथा आंवले का पाउडर 10 ग्राम लेकर एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह अच्छी तरह मिलाकर पी लें। इससे चक्कर आने बंद हो जाते है।

सिर चकराने पर आधा गिलास पानी में दो लौंग डालकर उसे उबाल लें और फिर उस पानी को पी लें। इस पानी को पीने से लाभ मिलता है।

10 ग्राम आंवला, 3 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम बताशे को पीस लें। 15 दिनों तक रोजाना इसका सेवन करें चक्कर आना बंद हो जाएगा।

जिन लोगों को चक्कर आते हैं उन्हें दोपहर के भोजन के 2 घंटे पहले और शाम के नाश्ते में फलों का जूस पीना चाहिए। रोजाना जूस पीने से चक्कर आने बंद हो जाएंगे। ध्यान रखें कि जूस में किसी प्रकार का मीठा या मसाला नहीं डालें सादा जूस पियें। जूस की जगह ताजे फल भी खा सकते हैं।

नारियल का पानी रोज पीने से भी चक्कर आने बंद हो जाते है।

चाय व कॉफ़ी कम पीनी चाहिए अधिक चाय व कॉफ़ी पीने से भी चक्कर आते हैं।

20 ग्राम मुनक्का घी में सेंककर सेंधा नमक डालकर खाने से चक्कर आने बंद हो जाते है।

खरबूजे के बीजों को पीसकर घी में भुन लें इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा सुबह शाम लें, इससे चक्कर आने की समस्या में बहुत लाभ होता है।

सभी सुखी और निरोगी रहे

विजय विश्वास से

प्रभु कृपा के बल के साथ ही जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय के लिए स्वयं पर विश्वास होना आवश्यक है। जीवन में सफल होने का एक सीधा सा मंत्र है और वो ये कि हमारी आशा स्वयं से होनी चाहिए किसी और से नहीं।

सूर्य स्वयं के प्रकाश से चमकता है और चन्द्रमा को चमकने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहना होता है। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने की आशा रखने के कारण ही चन्द्रमा की चमक एक जैसी नहीं रहती।

कमल उतनी ही देर अपना सौंदर्य बिखेरता है जितनी देर उसे सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। जीवन में सफल एवं सदा खुश रहना है तो दूसरों से किसी भी प्रकार की आशा छोड़कर प्रभु कृपा के बल का भरोसा बनाए रखे।

इस पूरी दुनिया में केवल एक ही मनुष्य हमारा भाग्य बदल सकता है। इस पूरी दुनिया में केवल एक मनुष्य ही हमारे हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान निकाल सकता है और वो कोई दूसरा नहीं केवल और केवल हम हैं।

हम ही इस दुनिया के वो इकलौते व्यक्ति हैं जो अपना भाग्य बदलने की सामर्थ्य रखते है। हम ही इस दुनिया के वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

हमारे अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं जिसके पास हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो। शांति पूर्वक मनन से स्वतः अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जायेगा।

!!!'बदलाव यदि हित में हो तो अवश्य बदल जाना चाहिए'!!!

हम बदलें तो दुनिया बदले

बेटियों के बलात्कारियों से जब माँ ने कहा "अब्दुल अली एक-एक करके करो, नहीं तो वो मर जाएंगी

8 अक्टूबर 2001 को बांग्लादेश में ये सच्ची घटना घटित हुई थी। पं.अनिल चंद्र और उनका परिवार 2 बेटीयों पूर्णिमा व 6 वर्षीय छोटी बेटी के साथ बांग्लादेश के सिराजगंज में रहता था। उनके पास जीने खाने और रहने के लिए पर्याप्त जमीन थी।

बस एक गलती उनसे हो गयी, और ये गलती थी एक हिंदु होकर 14 साल व 6 साल की बेटी के साथ बांग्लादेश में रहना। एक क़ाफिर के पास इतनी जमीन कैसे रह सकती है..?

यही सवाल था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद ज़िया के पार्टी से सम्बंधित कुछ उन्मादी लोगों का।

8 अक्टूबर के दिन अब्दुल अली, अल्ताफ हुसैन, हुसैन अली, अब्दुर रउफ, यासीन अली, लिटन शेख और 5 अन्य लोगों ने अनिल चंद्र के घर पर धावा बोल दिया, पं अनिल चंद्र को मारकर डंडो से बाँध दिया, और उनको काफ़िर कहकर गालियां देने लगे।

इसके बाद ये शैतान माँ के सामने ही उस १४ साल की निर्दोष बच्ची पर टूट पड़े और उस वक्त जो शब्द उस बेबस लाचार मां के मुँह से निकले वो पूरी इंसानियत को झंकझोर देने वाले हैं।

अपनी बेटी के साथ होते इस सामूहिक अत्याचार को देखकर बेबस लाचार मां ने अपनी बच्ची को हैवानों से बचाने के लिए कहा "अब्दुल अली, अल्ताफ हुसैन, हुसैन अली, अब्दुर रउफ, यासीन अली, लिटन शेख एक एक करके करो, नहीं तो मेरी बच्ची मर जाएगी, वो सिर्फ 14 साल की है।"

यह सुनकर भी वो हैवान यहीं नहीं रुके उन माँ बाप के सामने उनकी छोटी 6 वर्षीय बेटी का भी सभी ने मिलकर बलात्कार किया और उनलोगों को वही मरने के लिए छोडकर जाते जाते आस पड़ोस के लोगों को धमकी देकर गए की कोई इनकी मदद नहीं करेगा।"

ये पूरी घटना बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी किताब "लज्जा" में लिखी जिसके बाद से उनको देश छोड़ना पड़ा, ये पूरी घटना इतनी हैवानियत से भरी है पर आजतक भारत में किसी बुद्धिजीवी ने इसके खिलाफ बोलने की हैसियत तक नहीं दिखाई है, ना ही किसी मीडिया हाउस ने इस पर कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत जुटाई।

ये होता है किसी इस्लामिक देश में हिन्दू या कोई अन्य अल्पसंख्यक होने का, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। पता नहीं कितनी पूर्णिमाओं की ऐसी आहुति दी गयी होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसँख्या को 25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत और पाकिस्तान में 23 प्रतिशत से 1 प्रतिशत पहुँचाने में।

और हिंदुस्तान में हामिद अंसारी जैसे घिनौने लोग कहते है कि हमें डर लगता है।

जबकि, हमारे देश में उनकी आबादी आज़ादी के बाद से 25 प्रतिशत अधिक बढ़ी है और आज भी बांग्लादेशी घुसपैठिये बसते जा रहे हैं।

अगर आप भी सेक्युलर हिंदु (स्वघोषित बुद्धिजीवी) हैं और आपको भी लगता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो कभी बांग्लादेश या पाकिस्तान की किसी पूर्णिमा को इन्टरनेट पर ढूंढ कर देखिये। बेबस और लाचार बच्चियों की तड़पती माँ ओं का खौफनाक सच जानकर दावा है कि आपका भी नजरिया बदल जाएगा!

सभी किराएदारों को बिजली-पानी पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा और उनको समान अधिकार और सुविधाएं दी जाएंगी- केजरीवाल

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पाटी की सरकार बनने के बाद किराए के मकान में रह रहे सभी लोगों को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली और 20 हजार लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। शनिवार को ''आप'' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किराएदारों को यह गारंटी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर मुफ़्त बिजली-पानी का फ़ायदा हर किराएदार को मिलेगा, उन्हें भी सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। यह केजरीवाल की गारंटी है कि हर किरायेदार को समान अधिकार और सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए हम योजना लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली और 20 हजार लीटर पानी प्रतिमाह देती है। दिल्ली में किराए पर रहे रहे पूर्वांचल समाज के लोगों को अच्छे स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के साथ ही फ्री बिजली और पानी का लाभ भी मिलने लगेगा।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं दिल्ली में जगह-जगह घूम रहा हूं। दिल्ली के लोगों के लिए हमने बिजली और पानी फ्री किया हुआ है। दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट बिजली हाफ रेट पर बिजली मिलती है और 20 हजार लीटर पानी हर महीने फ्री मिलता है। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किरायेदारों को फ्री बिजली और पानी का लाभ नहीं मिलता। इसके अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं। उनको भी फ्री बिजली और पानी का फायदा मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, वहां किराएदार मुझे घेर लेते हैं और कहते हैं कि आपके अच्छे स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त तीर्थ यात्रा का हमें फायदा मिल रहा है, लेकिन आपके मुफ्त बिजली और पानी का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए आज मैं एलान करता हूं कि चुनाव के बाद हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसी योजना लेकर आएंगे और ऐसा सिस्टम बनाएंगे, जिससे किरायेदारों को भी फ्री बिजली और पानी का फायदा मिलना चालू हो जाएगा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सभी किराएदारों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल से आने वाले लोग किराए पर रहते हैं। वह बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा है कि कई बार एक-एक बिल्डिंग में 100 लोग रह रहे होते हैं। इतनी गरीबी की हालत में भी अगर उनको सब्सिडी और सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है तो उन्हें आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन सब लोगों को भी फ्री बिजली और पानी का लाभ मिलना चालू हो जाएगा।

केजरीवाल की अन्य प्रमुख गारंटियां*

महिला सम्मान राशि योजना,संजीवनी योजना*,पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना*,छात्रों को बसों में मुफ्त यात्रा और मेट्रो किराए में रियायत*,दिल्ली के ऑटो वालों को पांच गारंटी*,डॉ. अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना,पानी के बिल होंगे माफ, आरडब्ल्यूए को सुरक्षा गार्ड रखने को मिलेगा फंड*

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सभी आरडब्ल्यूए को अपनी सोसायटी में सुरक्षा गार्ड रखने के लिए सरकार की तरफ से फंड देने की गारंटी दी है। दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है, लेकिन केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में बुरी तरह विफल रही है। जिससे अपराध बढ़ गए हैं। इसके मद्देनजर ''आप'' की सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार आरडब्ल्यूए को सुरक्षा गार्ड तैनात करने के लिए फंड देगी।

मुरलीकांत पेटकर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया: उनकी कहानी को फिल्म के रूप में जीवंत करने के लिए साजिद नाडियाडवाला का आभार

सुषमा रानी

नई दिल्ली। भारत के पहले पैरालिंपिक स्वर्ण पदक विजेता, महान मुरलीकांत पेटकर की कहानी को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के प्रमुख साजिद नाडियाडवाला ने बड़े पर्दे पर जीवंत किया। हाल ही में पेटकर को उनकी उपलब्धि के 52 साल बाद अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) से सम्मानित किया गया.

इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को प्राप्त करने पर मुरलीकांत पेटकर ने कहा, "मैं प्रतिष्ठित अर्जुन लाइफटाइम अवार्ड प्राप्त करने के लिए वास्तव में अभिभूत और बहुत आभारी हूं। यह सम्मान केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह कई अच्छे व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास और विश्वास का प्रमाण है। मैं साजिद नाडियाडवाला का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने न केवल मेरी कहानी पर विश्वास किया, बल्कि इसे फिल्म चंदू चैंपियन के माध्यम से बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए अपना भरोसा और संसाधन लगाए। उनके अडिग समर्थन ने सब कुछ बदल दिया। मैं कबीर खान के प्रयासों का भी उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी यात्रा को सबसे प्रामाणिक तरीके से बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया। और कार्तिक को, जिन्होंने मेरी कहानी को बेहतरीन ढंग से पेश किया। यह क्षण जितना मेरा है, उतना ही उनका भी है, मैं वास्तव में पूरी चंदू चैंपियन की टीम का आभारी हूं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया और मेरी कहानी के माध्यम से देश के कई लोगों को प्रेरित किया।"

खेलों में एक ऑलराउंडर, मुरलीकांत पेटकर ने पैरा-स्विमिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करने से पहले कई खेलों में प्रतिस्पर्धा की। वह ऐतिहासिक सफलता और साहस के सच्चे प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

यह फिल्म ''आप'' नेताओं को गलत तरीके से जेल भेजने के पीछे के रहस्यों और भाजपा के गैर कानूनी कामों को उजागर करती है : केजरीवाल

सुषमा रानी

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी पर बनी फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग को रूकवाने पर पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। ''आप'' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर बनी फिल्म से भाजपा इतनी डर गई है कि उसने पुलिस भेज कर फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग को रूकवा दिया। आखिर इस फ़ल्मि में ऐसा क्या है, जिससे भाजपा डरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म आम आदमी पार्टी के नेताओं को गलत तरीके से जेल भेजने के पीछे के रहस्यों और भाजपा के असंवैधानिक व गैर कानूनी कामों को उजागर करती है। इस फ़ल्मि का चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद इसे दिखाने से रोकना गुंडागर्दी और तानाशाही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म को देश भर के सिनेमा घरों में दिखाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली गई थी?

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। शनिवार को पत्रकारों के लिए उस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। लेकिन आज सुबह दिल्ली पुलिस ने वहां पहुंचकर फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि यह स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। जबकि यह एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत इसकी इजाजत नहीं है कि पुलिस इस तरह से किसी फिल्म के स्क्रीनिंग रुकवा दे। यह कोई चुनाव का कैंपेन नहीं था। वहां कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, इलेक्शन की स्पीच नहीं थी। किसी पार्टी के लिए वोट की अपील नहीं की जा रही थी और ना ही चुनाव प्रचार किया जा रहा था। वहां किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था और ना ही किसी पार्टी के खिलाफ बोला जा रहा था। यह फिल्म की एक निजी स्क्रीनिंग थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा इस फिल्म से इतनी क्यों डरी हुई है? हालांकि, मैंने तो यह फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर पिछले दो सालों में जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा गया, यह उनके जेल भेजे जाने के पीछे की कहानी है। यह फिल्म कई सारे रहस्यों और षडयंत्रों से पर्दा उठाती है। भाजपा ने जिस तरह असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं जेल भेजा था, उस पर से यह फिल्म पर्दा उठाती है इसलिए भाजपा इतनी ज्यादा डरी हुई है। इस फिल्म को जिस तरीके से रोका गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस फिल्म को दिखाने की इजाजत दी जाएगी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए चुनाव आयोग से इजाजत लेनी पड़ेगी। यह तो चुनाव का कार्यक्रम ही नहीं है। पुलिस को बहुत समझाया गया। इस फिल्म का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल गुंडागर्दी और तानाशाही है। मुझे उम्मीद है भविष्य में यह फिल्म सबके लिए आएगी। भाजपा के कुकर्मों के बारे में सबको पता चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली बार विवेक अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिल्म बनाई गई थी, जिसे देश भर के सिनेमाघरों में दिखाया गया था। क्या उसके लिए चुनाव आयोग की इजाजत ली गई थी

उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी पर एक फ़ल्मि बनी है। आज जहां इस फ़ल्मि को पत्रकारों को दिखाया जाना था, वहां देखिए, कितनी भारी संख्या में पुलिस लगाकर भाजपा ने इस फ़ल्मि को दिखाने से रोक दिया। भाजपा इस फ़ल्मि से बुरी तरह से डरी हुई है। आख़िर क्यों? भाजपा इस फ़ल्मि को क्यो रोकना चाहती है? इस फ़ल्मि में आखिर ऐसा क्या है, जिससे भाजपा डरी हुई है? ये फ़ल्मि पर्दे के पीछे के उन सब रहस्यों को उजागर करती है जब ग़लत तरीक़े से "आप" के नेताओं को गिरफ़्तार किया गया था। यह भाजपा सरकार के ग़ैर क़ानूनी और ग़ैर संवैधानिक कामों को उजागर करती है।

लाल सिंह आर्य ने कहा आपदा से दिल्ली वासियों को बचाना है

सुषमारानी, नई दिल्ली। नरेला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार राजकुमार खत्री के समर्थन में भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा - द्वारा आयोजित दलित_स्वाभिमान_सम्मेलन को संबोधित किया और धोखेबाज,घोटालेबाज आप पार्टी को हराकर,भाजपा को जिताने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने भी संबोधित किया। उत्तरप्रदेश के विधायक उमेश मलिक,जिलाध्यक्ष मुकेश कादियान पूर्व पार्षद अर्चना दिलीप सिंह,अजा विस्तार ललित लकवाल एवं अशोक अमरोही सहित प्रमुख नेतागण उपस्थित रहे। *लाल सिंह आर्य ने बोलते हुए कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाते हुए कहा कि वह युद्ध स्तर पर कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को जनता के सामने बेनकाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उसके प्रत्याशी को विजई बनाएं।

इस मौके पर हुए कहा कि हम *

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान भगवान राम में आस्था रखते हैं हम तो अपने प्रत्येक *भाजपा कार्यकर्ता को भी देवतुल्य मानते हैं और मैं अपने उन्हीं देवतुल्य कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि युद्ध स्तर पर* *चुनाव मैदान में कूद जाएं और अपने-अपने प्रत्याशियों को चुनाव भारी मतों से*जीताकर लाए और दिल्ली को दिल्ली वासियों को आपदा से बचाए क्योंकि इस आपदा ने पूरी दिल्ली को तहस-नहस कर दिया है* *लाल सिंह आर्य ने कहा कि क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रत्याशी कमल का निशान है और हमें कमल के प्रत्याशी और कमल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट डलवा कर अपने प्रत्याशी को विजयश्री दिलाते हुए भाजपा की सरकार बनानी है।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने हमास और इजरायल युद्धविराम समझौते का किया स्वागत

MEDIA DEPARTMENT

सुषमा रानी

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अमीर (अध्यक्ष) सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने इजरायल और हमास के बीच हाल ही में घोषित युद्धविराम समझौते का स्वागत किया है। मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत अध्यक्ष ने कहा, ₹यह युद्धविराम गजा में रक्तपात को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे गजा के लोगों को बुनियादी राहत पहुंचाने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने इतिहास के विनाशकारी नरसंहार हमलों को सहन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गजा के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए तत्काल प्रयास शुरू करने चाहिए तथा अरब भूमि से इजरायली सेनाओं की पूर्ण वापसी की दिशा में निर्णायक कदम उठाने चाहिए, ताकि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।₹

जमाअत के अमीर अध्यक्ष ने "फिलिस्तीन के लोगों के साहसी और वीर प्रतिरोध और बलिदान को सम्मान अर्पित किया। उन्होंने वैश्विक शक्तियों को याद दिलाते हुए कहा, ₹यह युद्धविराम 15 महीने के क्रूर हमले के बाद आया है, जिसमें 48,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिनमें से अधिकांश बच्चे, महिलाएं, डॉक्टर, शिक्षक, राहत कार्यकर्ता, पत्रकार के अतिरिक्त निहत्थे नागरिक शामिल थे। गजा पर हमला तथाकथित सभ्य विश्व पर एक बड़ा दाग और इतिहास तथा मानवता की अंतरात्मा पर एक कांटा बना रहेगा।

सआदतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि यद्यपि युद्ध विराम रविवार से लागू होना है, लेकिन इजरायल ने हिंसा जारी रखी है, जिसके कारण इस बीच 21 बच्चों और 25 महिलाओं सहित 87 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा, ₹विश्व को यह समझना होगा कि इजरायल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों एवं मानवीय सिद्धांतों के प्रति घोर उपेक्षा क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।₹

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद मांग करती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल द्वारा किये गए घोर अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराए।उन्होंने कहा, ₹इस विनाश के लिए जिम्मेदार शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को उनके कृत्यों के लिए न्याय का सामना करना होगा, जो उन्होंने बिना किसी पश्चाताप के और दंड से मुक्त होकर किए।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्धविराम समझौते को अंतिम बिंदु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।₹स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए कब्जे और अन्याय के मूल कारणों को दूर किया जाना चाहिए। जमाअत -ए-इस्लामी हिंद एक स्वतंत्र एवं संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए अपना आह्वान दोहराती है। मध्य पूर्व में स्थायी शांति केवल फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय, फिलिस्तीनी प्रवासियों के लिए वापसी के अधिकार और अल-अक्सा मस्जिद और अल-कुद्स की पूर्ण मुक्ति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा, ₹हम वैश्विक समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह इन बुनियादी मुद्दों के समाधान के लिए निर्णायक कदम उठाए तथा सभी के लिए सह-अस्तित्व, सुरक्षा और स्थिरता के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे।"

दिल्ली के वायु, जल प्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार - संदीप दीक्षित

सुषमा रानी

नई दिल्ली। पूर्व सांसद, नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अरविन्द केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कोई काम नही किया है। खतरनाक दमघोटू वायु प्रदूषण और यमुना के प्रदूषित जहरीले पानी के कारण दिल्ली के लोगों की 10-11 वर्ष आयु कम हो रही है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है।

संवाददाता सम्मेलन में संदीप दीक्षित के साथ, मीडिया कॉआर्डिनेटर अभय दूबे, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार डा0 नरेन्द्र नाथ, आस्मा तस्लीम, रश्मि सिंह मिगलानी मौजूद थीं।

उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 64 कि0मी0 मंजूर करने के बाद यह कहना 400 कि0मी0 मेट्रो बढ़ाई है, लोगों को धोखा दे रहे है। उन्होंने कहा कि 2002 में पहले चरण और 2006 में दूसरे चरण में 193 कि0मी0 के रुट को मंजूरी मिली और 2011 में तीसरे चरण के लिए 164 कि0मी0 की मंजूरी मिली थी, जिसका काम 2015-16 में पूरा होना था। लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह काम 2023 तक भी पूरा नही किया। अरविन्द केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के चलते न डीटीसी बसें बढ़ाई, न मेट्रो का रुट बढ़ाया और न ही सड़कें बनाने का काम किया, जिससे प्रदूषण दमघोटू और खतरनाक बन गया है। उन्होंने कहा कि 2013 तक हमने 67-68 फ्लाई ओवर बनाकर सुगम यातायात देने के साथ ईंधन और समय बचाने में क्रांतिकारी काम किया था। जिससे 8400 करोड़ रुपये की बचत हुई और 56000 साल के समय की बचत हुई।

दीक्षित ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने 2014 से आज तक के शासन में फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए कोई काम नही किया। 2013 में जहां ग्रीन कवर 300 वर्ग कि0मी0 था आज भी सिर्फ 299 वर्ग कि0मी0 ही है। विज्ञापनां और प्रचार में बेशक केजरीवाल सरकार ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत में 2013 के मुकाबले आज फॉरेस्ट कवर लगभग उतना ही है, या कुछ कम हुआ है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना प्रदूषण लोगों के खराब स्वास्थ्य के लिए बड़ा कारण है। अरविन्द केजरीवाल जो यह कह रहे है कि हमने यमुना के 50 प्रतिशत पानी शोधित किया है। मैं पूछना चाहता हूॅ कि 2013 में कांग्रेस सरकार 920 एमजीडी जल शोधन करती थी और आज 940 एमजीडी पानी शोधित किया जा रहा है, अगर सच में 50 प्रतिशत अधिक जल शोधित किया जा रहा है तो दिल्ली के लोगां को पानी क्यों कम पड़ रहा है। एनडीएमसी क्षेत्र लुटियन जोन में पानी क्यों नही मिल रहा है। अरविन्द केजरीवाल ने पिछले 8 वर्षों में एक भी जल शोधन सयंत्र नही बनाया है, वजीराबाद, औखला, बवाना जैसे बड़े जल सयंत्रों की जल शोधन की क्षमता को भी नही बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 2-3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर काम चला है।

दीक्षित ने कहा कि 2014 के बाद यमुना का जल दूषित हुआ है, जिसके लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है क्योंकि यमुना में मानव और जानवर को वेस्ट और केमिकल यमुना में अत्यधिक डाला जा.रहा है, सरकार को बड़े-बड़े सभी 6 नालों का गंदा पानी शोधित करके यमुना में छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के लिए मौजूदा सरकारें जिम्मेदार है।

अनुसूचित जाति के सभी वर्गों का उत्थान मेरे लिए जरूरी है: मोहन लाल गिहारा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल गिहारा ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि* *अनुसूचित जाति समाज के तमाम वर्गों का उत्थान जरूरी है मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि अपने* *अनुसूचित जाति समाज के लोगों का विकास हो और उनकी उन्नति हो*

पिछले 75 वर्षों से वर्षों से मेरे अनुसूचित जाति समाज का कांग्रेस तथा अन्य दलों के शासन काल में तिरस्कार होता चला आ रहा है यह देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि मेरे अनुसूचित जाति समाज से लोगों से कांग्रेस के शासनकाल में छुआ छात होता चला रहा है जिसका जिम्मेवार पिछले सालों में रही कांग्रेस में उनके सहयोगी दल हैं और अनुसूचित जाति समाज को कांग्रेस तथा उनके सहयोगी दोनों द्वारा जातिवाद में उलझा कर रखा हुआ हैं*

जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के उपरांत समाप्त किया गया है

मोहनलाल गिहारा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दलितों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया है और उनके विकास उनकी शिक्षा उनके रोजगार पर गंभीरता से विचार करते हुए उनका हल किया गया है आज अनुसूचित जाति समाज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निर्भीक व निडर होकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है और एक सम्मान का जीवन जी रहा है

प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल गिहारा ने कहा कि मेरा बच्चा कुछ जीवन अपने अनुसूचित जाति समाज के तमाम वर्गों को न्याय व अधिकार दिलाना ही जीवन का मकसद है

नोएडा से लापता हुए चारों छात्र मिले, घर जाने से किया मना; भागने की असली वजह आई सामने

नोएडा से लापता हुए चारों छात्रों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि छात्रों ने योजना बनाकर ग्वालियर भागने की कोशिश की थी। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद तीन छात्र उसे छोड़कर चले गए। चौथे छात्र ने अपने स्वजन को दिल्ली में होने की सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने उसे और अन्य तीनों छात्रों को सकुशल बरामद कर लिया।

ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र स्थित बालक इंटर कॉलेज से लापता चारों छात्रों को पुलिस ने सकुशल पकड़ लिया है। एक छात्र को पुलिस से शुक्रवार की सुबह पकड़ा था। उससे पूछताछ करने पर तीन अन्य फरार छात्रों तक पुलिस ने पहुंचने में कामयाबी हासिल की।

हालांकि खबर लिखे जाने तक छात्रों को दिल्ली से ग्रेटर नोएडा लाया नहीं जा सका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि योजना बनाकर चारों छात्र ग्वालियर भाग गए थे। वहां से दिल्ली पहुंचे और कहीं और जाने की योजना बनाई। पुलिस को मिले एक छात्र ने वापस घर चलने की बात कही जिसे तीन अन्य छात्रों ने नकार दिया।

दिल्ली स्टेशन पर उसे अकेला छोड़कर तीनों छात्र रवाना

छात्रों ने पिटाई की आशंका जताते हुए घर आने से इनकार कर दिया। छात्र से पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि दिल्ली स्टेशन पर उसे अकेला छोड़कर तीनों छात्र रवाना हो गए। छात्रों ने उसे भी नहीं बताया कि कहां जा रहे हैं।

वहीं तीनों के जाने के बाद चौथे छात्र ने अपने स्वजन को दिल्ली में होने की सूचना दे दी। स्वजन की सूचना पर पुलिस भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। और छात्र के साथ देर शाम को अन्य तीनों छात्रों को भी सकुशल बरामद कर लिया।

छात्रों के गायब होने के बाद से स्वजन थे परेशान

ज्ञात हो कि बुधवार की सुबह चारों छात्र स्कूल से फरार हो गए थे। काफी तलाश करने के बाद भी जब बच्चों का पता नहीं चला तो स्कूल प्रबंधन पुलिस के साथ ही स्वजन को मामले की जानकारी दी। छात्रों के गायब होने के बाद से स्वजन परेशान थे।

पीड़ित स्वजन स्कूल के साथ कोतवाली पुलिस के चक्कर काट रहे थे। स्वजनों को बच्चों के साथ कोई अनहोनी की आशंका थी, लेकिन चारों छात्रों के मिलने के बाद पीड़ित स्वजन के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन ने राहत की सांस ली है।

स्वजन ने उठाया स्कूल की सुरक्षा पर सवाल

छात्रों के लापता हो जाने के बाद लगातार स्कूल में अन्य स्वजन अपने बच्चों से मिलने आ रहे हैं। वे स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं।

स्वजन का कहना है कि सीबीएससी के नियमों के अनुसार स्कूल में सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य है। उसके बावजूद स्कूल में अव्यवस्थाओं का आलम है। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे तो दूर सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त संख्या नहीं है।

डॉ. एस.पी. शर्मा (रिटायर्ड,AIIMS) को अखिल भारतीय विप्र एकता मंच का राष्ट्रीय महामंत्री/महासचिव किया नियुक्त

श्री शर्मा ने शुभकामनाओं के साथ आगे कहा,"आप मंच के उद्देश्यों व विचारधारा को प्रखर तरीके से आगे बढ़ाते हुए संगठन का विस्तार व मंच की समस्त प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व विधिक कार्यों में सक्रिय व महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। अखिल भारतीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ उमेश शर्मा ने मंच के सभी सम्मानित बंधुओं को आज़ सादर सूचित करते हुए बताया कि अखिल भारतीय विप्र एकता मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुमत सिद्ध निर्णयानुसार, मंच की पिछले कई महीनों से बंद पड़ी सामाजिक हित की गतिविधियों व पूर्व पदाधिकारियों द्वारा चुनाव के समाप्ति बाद ही स्वेच्छिक आधार पर मंच के कार्य शून्य स्थिति के कारण व इन सभी के निदान व संगठन को गतिशील बनाये रखने हेतु पं.(डॉ.) एस.पी.शर्मा (नि.उत्तम नगर,दिल्ली) को अखिल भारतीय विप्र एकता मंच का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया जाता है।

श्री शर्मा ने शुभकामनाओं के साथ आगे कहा, "आप मंच के उद्देश्यों व विचारधारा को प्रखर तरीके से आगे बढ़ाते हुए संगठन का विस्तार व मंच की समस्त प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व विधिक कार्यों में सक्रिय व महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। आगामी दिनों में आप सभी प्रादेशिक, संभागीय, जिलास्तरीय, तहसील व ब्लॉक स्तरीय इकाइयों के पुनर्गठन में भी कार्यकारिणी के सचिव व संगठन के महामंत्री के दायित्वानुसार कार्य करेंगे।"

अगर आपके मोबाइल में भी है आधार और पैन कार्ड, तो खाली हो सकता है बैंक खाता; पुलिस ने जारी की चेतावनी

नोएडा में मोबाइल लूटने के साथ ही शातिर यूपीआई का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। कई मामलों में मोबाइल लूटने के साथ-साथ यूपीआई से पैसे निकालने के केस सामने आए हैं। पुलिस लोगों से मोबाइल को लूटने से बचाने के साथ-साथ मोबाइल में पड़े दस्तावेजों को भी हिफाजत से रखने पर जोर दे रही है। लेख में जानें पूरी जानकारी।

नोएडा। मोबाइल लूट के दौरान शातिर दोहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोबाइल के साथ-साथ यूपीआइ का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। नोएडा में कई मामलों में मोबाइल लूटने के साथ-साथ यूपीआई से पैसे निकालने के कई केस सामने आ चुके हैं।

पुलिस लोगों से मोबाइल को लूटने से बचाने के साथ-साथ मोबाइल में पड़े दस्तावेजों को भी हिफाजत से रखने पर जोर दे रही है ताकि मोबाइल लूट के साथ-साथ साइबर ठगी होने से भी बचा जा सके।

केस नंबर एक

मोबाइल चोरी कर खाते से उड़ाए 98 हजार

ग्रेटर नोएडा के अमित ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि दो जनवरी की शाम को उनकी पत्नी अनुपमा जोडिएक मार्केट के साप्ताहिक बाजार में गईं थीं। खरीदारी के दौरान किसी शातिर ने पत्नी के जैकेट से मोबाइल फोन चोरी कर लिया।

काफी खोजबीन करने पर भी मोबाइल नहीं मिला। घर पहुंचने पर पता चला कि शातिरों ने यूपीआई की मदद से 98 हजार रुपये भी निकाल लिये हैं। थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

केस नंबर दो

झपटे अनलॉक मोबाइल से उड़ाए 1.50 लाख

सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 46 स्थित सदरपुर में स्कूटी सवार दो शातिर सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मी से मोबाइल झपट ले गए। पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपितों ने मोबाइल को अनलॉक ही रखा था।

मोबाइल की गैलरी में पड़े आधार कार्ड का दुरुपयोग कर यूपीआई का पिन चेंज कर दिया था। इससे शातिरों ने बैंक खाते से करीब 1.50 लाख रुपये चोरी कर लिये थे। अपने ही खातों में रुपये ट्रांसफर होने के कारण शातिर पकड़े गए थे।

डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह से बताया कि मोबाइल झपटमारी का शिकार होने वाले पीड़ितों के यूपीआई, बैंक खाते से भी शातिर धनराशि उड़ा रहे हैं। थोड़ी सी सतर्कता से ठगी होने से बचा जा सकता है।

मोबाइल में आधार कार्ड, पैन कार्ड (Pan Card) जैसे निजी दस्तावेजों को लॉक लगाकर रखा जाए, मोबाइल झपटमारी होते ही तत्काल सिम को बंद करा दें, ताकि शातिरों को मोबाइल नंबर, यूपीआई (Mobile UPI) व बैंक खाते का दुरुपयोग करने से रोका जा सके।

ऑफिस में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, सामने आई ये बड़ी वजह

फरीदाबाद में जमीन के विवाद ने एक युवक की जान ले ली। चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतक और आरोपी दोनों गांव फतेहपुर चंदीला के रहने वाले हैं। फिलहाल ओल्ड फरीदाबाद थाने की पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।

फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद थाने के अंतर्गत दिल्ली-मथुरा रोड स्थित एक आफिस में घुसकर प्रापर्टी डीलर की दो गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात बृहस्पतिवार देर रात की है। हत्या में मृतक का सगा भाई और चाचा भी शामिल बताए गए हैं। जबकि एक अन्य आरोपित भी साथ था।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपितों की तलाश जारी है। हत्या का कारण प्रापर्टी विवाद बताया जा रहा है। शुक्रवार दोपहर को मृतक के शव का पोस्टमार्टम बादशाह खान नागरिक अस्पताल में कराया गया। ओल्ड फरीदाबाद थाने में फतेहपुर चंदीला गांव में रहने वाले प्रदीप सिंह ने दी शिकायत में बताया कि वह दो भाई एक बहन है। वह और उसका भाई नरेंद्र प्रॉपर्टी डीलर हैं।

उनका आफिस दिल्ली-मथुरा रोड किनारे 16/5 में है। रात को वह नौ बजे अपने घर के लिए निकल गए। उस समय आफिस में भाई नरेंद्र, उसका दोस्त जसवंत सैनी और सहायक अंकित था। अंकित ने उसे फोन कर बताया कि आफिस में दो-तीन युवक आए और हमला कर दिया। यह सुनकर वह स्कूटी लेकर ऑफिस की तरफ भागे।

देखा कि मेवला गांव निवासी आशीष चपराना और फतेहपुर गांव निवासी उनका चाचा कुलदीप सिंह व भाई विकास गोली चलाते हुए भाग रहे हैं। गोली उनके भाई नरेंद्र की छाती में लगी थी और वह लहूलुहान था। वह उसे लेकर एशियन अस्पताल गए। जहां डाक्टरों ने भाई को मृत घोषित कर दिया।

हत्या का ठोस कारण सामने नहीं आया

उन्होंने बताया कि उनके भाई का विकास, कुलदीप व आशीष चपराना से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी वजह से उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। सेक्टर-19 पुलिस चौकी प्रभारी अजय ने बताया कि विकास को कुलदीप ने गोद लिया हुआ है। इसलिए वह उनके पास ही रहता है लेकिन विकास मृतक नरेंद्र का सगा भाई है। हत्या का ठोस कारण सामने नहीं आया है। मृतक के स्वजन से बात की जाएगी।

पता चला है कि लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर खींचतान चल रही थी।

आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। जल्द हाथ लग जाएंगे।

जमीन के विवाद में हमला, गोली चलाई

सेक्टर-58 थाने में बीजोपुर निवासी रसीद अहमद ने दी शिकायत में बताया कि उनकी कृषि भूमि बीजोपुर से जखोपुर वाले रास्ते पर है। वह सुबह अपने खेत पर गए। वहां देखा कि आदिल, नासिर, जाफर, हसीन, कामिल, लूकमन, साकिब, वसीम, तालिम व इनके साथ और अन्य लोग थे। उन्होंने आते ही उसे गाली दी और कहा कि यह जमीन उनकी है। आरोपितों के पास लाठी, डंडे व पिस्तौल थी। एक आरोपित ने पिस्तौल से गोली चला दी। यह देख वह भागा और अपनी जान बचाई। इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गोली चलाई, बाल-बाल बची महिला

सेक्टर-दो में रहने वाले राकेश कुमार ने अग्रसैन पुलिस चौकी में दी शिकायत में बताया कि 15 जनवरी की रात को वह और उनकी पत्नी अपने घर के बाहर घूम रहे थे। अचानक धमाके की आवाज आई। देखा तो वहां एक लोहे का टुकड़ा पड़ा था। अगले दिन लोगों ने बताया कि यह गोली का खोल है। उनके मकान के सामने खड़ी कार पर भी गोली के निशान लगे हुए थे।

इसकी सूचना डायल 112 पर दी। पुलिस ने आकर जांच की। ऐसी आशंका है कि किसी ने उन पर गोली चलाई लेकिन वह कार में लगी। जिसका खोल पत्नी को लगा। पत्नी को चोट नहीं आई। शुक्र रहा कि गोली महिला को नहीं लगी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।

मुझे फुर्सत नहीं-वित्तीय प्रलोभन का अवसर आ जाएगा तो मैं झट से टाइम निकाल लूंगा!

व्यस्त रहना अक्सर हमारे विचारों के अकेले होने की सुविधा के लिए बनाया गया एक बहाना होता है – एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - भारतीय सामाजिक संरचना हजारों वर्ष पुरानी है। विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करना और हमारे पूर्वजों बड़े बुजुर्गों द्वारा शाब्दिक तानों बानों में अनेक कहावतों की एक शाब्दिक संरचना कर डाली है, जो आज के इस आधुनिक डिजिटल युग में भी हम सटीक महसूस करते हैं जबकि हजारों वर्ष पूर्व तो इसकी शाब्दिक रचना करने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि इसकी सटीकता हजारों वर्ष के बाद भी प्रमाणित होते रहेगी !वैसे तो अनेक कहावतें हैं पर आज हम अपने आप को बहुत व्यस्त बताते हैं, हर बात पर कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बिजी हूं, मुझे फुर्सत नहीं, परंतु अगर वहीं पर मेरे बहुत काम का, फायदे का, किसी प्रकार की वित्तीय प्रलोभन का अवसर आ जाएगा तो मैं झट से टाइम निकाल लूंगा ! इसका अर्थ हजारों वर्ष पूर्व ही कहा गया था काम एक पैसे का नहीं फुर्सत एक मिनट की नहीं, काम बिल्कुल नहीं फिर भी समय नहीं, काम कौड़ी का नहीं फुर्सत ढेले की नहीं, बताते चलें कि कौड़ी और ढेला भारतीय मुद्रा की अत्यंत प्राचीनतम इकाई है कौड़ी थोड़ी छोटी और ढेला उससे बड़ी इकाई है, इसलिए हम इस कहावत सहित तमाम कहावतों, लोगोस, पंक्तियों पर जो इसपर आधारित है, असल में व्यस्त रहना अक्सर हमारे विचारों के अकेले होने की सुविधा के लिए बनाया गया एक बहाना है जो मानवीय स्वभाव बन गया है इसलिए आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से, मुझे फुर्सत नहीं है परंतु काम एक पैसे का नहीं फुर्सत एक मिनट की नहीं इस पर चर्चा करेंगे।

साथियों बात अगर हम मुझे फुर्सत नहीं की करें तो हम अक्सर अपने आसपास निरंतर यह सुनते रहते हैं कि वह शान से कहते हैं, मुझे फुर्सत नहीं, परंतु हम महसूस करते हैं कि यह कहने की बात है, फुर्सत तो निकल ही जाती है किसी ने खूब ही कहा है कि, बिजी होना पर्याप्त नहीं है बिजी तो चीटियां भी होती है सवाल उठता है हम कहां बिजी हैं यह शानदार विचार है। हमें इसका जवाब ढूंढना चाहिए।

साथियों बात अगर हम जिंदगी को फुर्सत देने की करें तो, जिंदगी को फुर्सत की जरूरत काम से कुछ कम नहीं है, लेकिन बेहिसाब ख्वाहिशें यह बात समझने नहीं देतीं। जो समझते हैं वे तमाम व्यस्तताओं के बावजूद समय निकालते हैं और इसे एक उत्सव की तरह मनाने के नित नए तरीके भी ईजाद कर लेते हैं। वाट्स ने लिखा है कि लोग पैसे बनाना और बचाना तो जानते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं, वे जिंदगी का आनंद लेने में असफल रहते हैं क्योंकि वे हमेशा जीने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक जीवित कमाई करने के बजाय वे अधिक कमाई कर रहे हैं, और इस प्रकार जब आराम करने का समय आता है तो वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। 70 वर्षों में भी कुछ बदला नहीं है।

साथियों बात अगर हम किसी के विचारों की करें तो, कुछ लोगों के लिए फुर्सत का मतलब चार दीवारों के दायरे से थोडा आगे बढकर बाहर निकल कर कुछ करना होता है। यह किसी बाजार या मॉल में जाकर शॉपिंग करना हो सकता है, किसी अजीज दोस्त या रिश्तेदार से मिलना हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाकर दो-चार हाथ आजमाने की कोशिश हो सकती है, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करना हो सकता है या फिर कुछ और, कुछ लोग योग या ध्यान के शिविर में चले जाते हैं, शरीर और मन दोनों को हलका करने, दोनों के विष निकाल कर खुद को बिलकुल नया कर लेने के लिए। जिसकी जैसी भी पसंद हो, उसी के अनुरूप वह अपने लिए अपने दैनिक रुटीन से अलग हटकर कोई काम ढूंढ लेता है। ऐसा काम जो उसे उसके रोज के टाइट शेड्यूल से थोडा ढीला होने का मौका देता है। यह ढीला होना उसके लिए ऐसे ही होता है जैसे दिन भर की भागदौड के बाद पांव पसारना !

साथियों बात अगर हम फुर्सत के चाहत की करें तो,अपने शौक पूरे करने से लेकर सपनों का संसार बसाने और आराम से जीने भर के लायक धन कमाने तक के लिए काम करना तो सभी चाहते हैं, पर काम के साथ-साथ फुर्सत की चाहत भी सबके भीतर होती है। फुर्सत की चाहत का यह मतलब बिलकुल नहीं कि 'आराम बडी चीज है, मुंह ढक के सोइए वाली पोजीशन में आ जाएं। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यह मतलब भी हो और वैसे भी दिन-रात पसीना बहाते इंसान के लिए जरा से आराम की चाहत कोई गुनाह थोडे ही है। बहुत लोगों के लिए आराम का मतलब भी मुंह ढक के पड रहना नहीं होता। उनके लिए इसका मतलब बस घर में बैठे-बैठे कुछ-कुछ करते रहना होता है। कुछ-कुछ यानी कभी किसी कमरे को नए सिरे से सजाना तो कभी कोई किताब पढना, बहुत दिनों से अधूरी पडी किसी पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश या हारमोनियम-तबला लेकर बैठ जाना, किसी भूली-बिसरी धुन पर सिर धुनना और कोई सिरा पकड में आ जाने पर उसी की मस्ती में खो जाना, ऐसा कुछ भी या इससे भी भिन्न कुछ और, बस घर में बैठे-बैठे करते रहना। संस्कृति के श्लोक में भी आया है कि

पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा मुन्मत्तभूतं जगत॥सूर्य् के अवागमन से दिनबदिन इन्सान की जिंदगी कम होती जाती है।व्यापार/व्यवसाय के काम में व्यस्त समय कब निकल जाता है, उसका ध्यान नहीं रहेता।जन्म, जरा (बुढापा), विपत्ति और (साक्षात) मृत्यु देखकर भी हमें डर नहीं लगता !

गुजर गया आज का दिन पहले की तरह

ना उनको फुर्सत थी ना हमें ख्याल आया है

मैं व्यस्त हूं यह झूठ अब बड़ा सच बन गया है

सबको अपने से मतलब है इसलिए सब व्यस्त हैं

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मुझे फुर्सत नहीं, काम एक पैसे का नहीं फुर्सत एक मिनट कि नहीं, व्यस्त रहना अक्सर हमारे विचारों के अकेले होने की असुविधा के लिए बनाया गया एक बहाना होता है।

आम आदमी पार्टी तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करेगी, सोचा हम ही आपको उनके काम

दिल्ली विधानसभा चुनावों को एक बार फिर जीतने के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी वोट मांगने के दौरान अपनी मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में तो जनता को बता ही रही है साथ ही वह संविधान और लोकतंत्र की दुहाई भी दे रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से दी गयी मुफ्त की सौगातें बड़ा छलावा साबित हुई हैं और लोकतंत्र तथा संविधान की मर्यादा का भी इस पार्टी की सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा।

आप देख रहे होंगे कि आजकल अरविंद केजरीवाल रोज प्रेस के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले पांच सालों में इन्होंने कुछ काम नहीं किया और सारा वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से लड़ने में बर्बाद कर दिया। जिस विधानसभा को दिल्ली के लोगों की समस्याओं का हल निकालना था उसको आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का मंच बनाकर रख दिया। दिल्ली विधानसभा को किस तरह आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का मंच बना कर रखा इसे आप इसी से समझ सकते हैं कि निवर्तमान विधानसभा ने पूरे पांच साल में मात्र 74 दिन ही कार्य किया। पांच साल में 1825 दिन होते हैं मगर इनमें से काम हुआ मात्र 74 दिन। हम आपको बता दें कि यह दिल्ली की विधानसभा के अब तक के सबसे कम कार्य दिवस का रिकॉर्ड है। इसके अलावा बड़ी-बड़ी बातें करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे पांच साल में मात्र 14 विधेयक पारित किये। यानि दिल्ली की विधानसभा ने अपने इतिहास में पांच साल में सबसे कम विधेयक पारित करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। खास बात यह रही कि यह जो 14 विधेयक पारित हुए उनमें से पांच विधायकों के भत्ते, सुविधाएं और उन्हें मिलने वाली सैलरी से संबंधित थे। साथ ही दिल्ली के विधायकों के कामकाज का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 से 2025 तक विधायकों ने विधानसभा में सालाना आधार पर औसत 219 प्रश्न ही पूछे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के शासन में विधानसभा में जिस दिन भी कार्यवाही हुई वह औसतन मात्र तीन घंटे तक चली। इसके अलावा विधानसभा के 74 कार्य दिवसों में से मात्र नौ दिन ही प्रश्नकाल हुआ।

यही नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी विधानसभा का सत्रावसान भी नहीं किया ताकि जब चाहें विधानसभा की बैठक बुला सकें और वहां से राजनीतिक बयानबाजी कर सकें। दरअसल विधानसभा का सत्रावसान होने पर सत्र को दोबारा आहूत करने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति चाहिए होती है और उन्हें सदन की बैठक बुलाने का कारण भी बताना होता है। आम आदमी पार्टी को लगता था कि यदि उपराज्यपाल ने बैठक बुलाने की अनुमति नहीं दी तो कैसे अपने राजनीतिक हित सधेंगे इसलिए वह कभी सत्रावसान करते ही नहीं थे। यही नहीं, विधानसभा में सीएजी की जो रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी थीं वह भी नहीं की गयीं।

जहां तक आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से बांटी जाने वाली मुफ्त रेवड़ियों की बात है तो उसकी सच्चाई यह है कि जनता को जितना दिया नहीं गया उतना हर योजना में घोटाला हो गया है। यह घोटाले भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके के हैं। मसलन एक दारू की बोतल पर दूसरी बोतल फ्री दी गयी लेकिन शराब नीति के जरिये घोटाला करके दिल्ली के सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गयी लेकिन एक यूनिट फालतू होते ही भारी भरकम बिजली बिल भेजे गये। जनता को 700 लीटर पानी फ्री देने की बात हुई लेकिन लोगों के भारी भरकम पानी के बिल आये। खास बात यह रही कि पानी का बिल तो हर महीने आ गया लेकिन नल से जल हर रोज नहीं आया और जहां जहां नल से जल आया वह गंदा आया।

इसके अलावा प्रदूषण से निबटने की कोई स्थायी और प्रभावी योजना नहीं होने के चलते दिल्ली इतनी प्रदूषित हो गयी कि लोगों को तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो गयी हैं। अक्सर बुजुर्गों को होने वाली सांस की बीमारी दिल्ली के बच्चों को भी हो गयी है। दिल्ली में पवित्र यमुना नदी को गंदा नाला बनने से रोकने में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल रही। दिल्ली में यमुना का जल इतना प्रदूषित है कि त्योहारों पर श्रद्धालु अगर पानी में चले जायें तो उन्हें चर्म रोग हो जाते हैं और इस पानी का शोधन करने में मशीनों के हाथ पांव फूल जाते हैं। यही नहीं, दिल्ली की सरकार अपने शिक्षा मॉडल का ढिंढोरा खूब पीटती है लेकिन अपने अब तक के कार्यकाल में वह एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज या एक भी नया अस्पताल नहीं बना सकी है। दिल्ली में जल निकासी की व्यवस्था इतनी खराब है कि बारिश आने पर बेसमेंट में पानी भर जाने से छात्र डूब कर मर जाते हैं। यही नहीं, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी का शासन होने के बावजूद कूड़े के पहाड़ वहीं के वहीं हैं।

इसके अलावा, अरविंद केजरीवाल भले इस समय मंदिर मंदिर जाकर हिंदुओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन तथ्य यह है कि आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान ही हिंदू दीवाली पर पटाखे नहीं चला पाये। यह बात भी गौर करने लायक है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को अभी 1000 रुपए मासिक देने और चुनाव बाद 2100 रुपए देने की बात कर रही है लेकिन सवाल उठता है कि महिलाओं की सुध उसे अपने शासन की शुरुआत या मध्य में क्यों नहीं आई थी ? यही नहीं, एक दारू की बोतल पर दूसरी दारू की बोतल फ्री देकर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं का ही सिरदर्द सबसे ज्यादा बढ़ाया था।

जेएसडब्ल्यू एमजी ने ऑटो एक्सपो में पेश की नई मैजेस्टर एसयूवी, डी प्लस सेगमेंट में जल्द होगी लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

MG Majestor unveiled in Auto Expo 2025 ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में एक और एसयूवी को पेश कर दिया गया है। कंपनी की ओर से Auto Expo 2025 के दूसरे दिन डी प्लस सेगमेंट में नई एसयूवी JSW MG Majesor को पेश किया गया है। इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा। किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से Bharat Mobility 2025 के तहत आयोजित किए गए Auto Expo 2025 के दूसरे दिन JSW MG की ओर से नई एसयूवी को पेश किया गया है। इस एसयूवी को किस सेगमेंट में किस तरह के फीचर्स के साथ लाया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

JSW MG ने पेश की नई एसयूवी

JSW MG मोटर्स की ओर से भारत में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नई एसयूवी JSW MG Majestor को पेश कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। साथ ही इसे काफी दमदार इंजन के साथ लाया जाएगा।

कैसे हैं फीचर्स

JSW MG Majestor एसयूवी में कंपनी की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को दिया है। इसमें एलईडी लाइट्स, कनेक्टिड टेल लैंप, सिंगल पेन सनरूफ, तीन रो, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयरबैग, एबीएस, ईबीडी जैसे कई फीचर्स को दिया गया है। इसके अलावा इसमें Level-2 ADAS जैसे कई फीचर्स को दिया जाएगा। कंपनी की ओर से अभी इस गाड़ी के इंजन, डायमेंशन आदि की जानकारी नहीं दी है। लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी।

किनसे होगा मुकाबला

भारत में एमजी की ओर से नई एसयूवी JSW MG Majestor को डी प्लस सेगमेंट में लाया गया है। इस सेगमेंट में फिलहाल भारत में और किसी कंपनी की ओर से किसी गाड़ी को ऑफर नहीं किया जाता है। ऐसे में एमजी ने नए सेगमेंट में इस गाड़ी को पेश किया है। लेकिन इसे अपनी की कंपनी की JSW MG Gloster, Toyota Fortuner जैसी एसयूवी से चुनौती मिल सकती है।

कितनी है कीमत

एमजी की ओर से नई एसयूवी को फिलहाल पेश किया गया है। इस दमदार एसयूवी को कुछ महीनों के दौरान भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। तभी इसकी कीमतों की जानकारी दी जाएगी।

बीवाईडी ने ऑटो एक्सपो 2025 में पेश की सीलियन 7 इलेक्ट्रिक एसयूवी, जानें कैसे हैं फीचर्स और कब होगी कीमतों की घोषणा

परिवहन विशेष न्यूज

BYD Sealion 7 in Auto Expo 2025 चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD की ओर से भारतीय बाजार में Auto Expo 2025 के तहत दो नई Electric SUVs को पेश कर दिया है। कंपनी की ओर से इनमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कब तक इसकी कीमत की घोषणा की जाएगी। कब से बुकिंग और डिलीवरी शुरू होगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। चीन की प्रमुख वाहन निर्माता BYD की ओर से भारतीय बाजार में Sealion 7 को पेश कर दिया गया है। Bharat Mobility 2025 के तहत आयोजित किए जा रहे Auto Expo 2025 के दौरान कंपनी की ओर से किन कारों को शोकेस किया है। इनके लिए बुकिंग को कब से शुरू किया जाएगा। पेश की गई Sealion7 की कीमत की घोषणा कब की जाएगी और डिलीवरी कब से शुरू होंगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

BYD ने पेश की दो Sealion7 Electric SVU

बीवाईडी की ओर से भारतीय बाजार में Auto Expo 2025 के दौरान नई Electric SUVs को पेश कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इसमें कई बेहतरीन फीचर्स दिए है और दमदार बैटरी के साथ लंबी रेंज दी गई है।

कौन सी एसयूवी हुई पेश

कंपनी की ओर से Auto Expo 2025 के दौरान BYD Sealion7 को पेश किया गया है। 17 फरवरी को कीमतों का एलान किया जाएगा।

कैसे हैं फीचर्स

BYD Sealion 7 इलेक्ट्रिक एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें 12 स्पीकर, वायरलेस फोन चार्जर, वॉटर ड्रॉप टेल लैंप, व्हीकल टू लोड, 15.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, नापा लैदर सीट, 128 कलर एंबिएंट लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

कितनी दमदार बैटरी

कंपनी की ओर से इसमें 82.56 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। गाड़ी को सिर्फ प्रीमियम और परफॉर्मेंस वेरिएंट्स में लाया गया है। इसमें लगी मोटर से इसे 390 किलोवाट की पावर और 690 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। गाड़ी में लगी मोटर से इसे 4.5 सेकेंड में ही 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है। सिंगल चार्ज में इसे 567 किलोमीटर की अधिकतम रेंज मिलती है। गाड़ी के साथ कंपनी 7KW की क्षमता का चार्जर दिया जाएगा।

कितनी है कीमत

कंपनी की ओर से Sealion 7 इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत की जानकारी अभी नहीं दी गई है। लेकिन इसकी बुकिंग को 18 जनवरी 2025 से शुरू कर दिया गया है। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी कीमतों की घोषणा 17 फरवरी 2025 को की जाएगी। अभी बुक करने पर कंपनी की ओर से स्पेशल बेनिफिट्स को दिया जाएगा। 70 हजार रुपये में एसयूवी को बुक करवाया जा सकता है।

ऑटो एक्सपो 2025 में नई बीएमडब्ल्यू X3 लॉन्च, डिजाइन से लेकर फीचर्स तक सब कुछ मिला नया

परिवहन विशेष न्यूज

4th जनरेशन BMW X3 को भारत में Auto Expo 2025 में लॉन्च कर दिया गया है। इसे पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है। इसके साथ ही BMW X3 में नए फीचर्स भी दिए गए हैं। नई X3 में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें अपहोल्स्ट्री और पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है।

नई दिल्ली। ऑटो एक्सपो 2025 में नई BMW X3 को लॉन्च कर दिया गया है। यह 4th जनरेशन की BMW X3 है। इसे नया डिजाइन के साथ ही नए फीचर्स से भी लैस किया गया है। इसे कंपनी X3 20d डीजल और X3 20 पेट्रोल के रूप में बेचा जाएगा। इसका इंटीरियर पहले ज्यादा प्रीमियम और शानदार दिया गया है। आइए जानते हैं कि नई BMW X3 किन नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है।

नई BMW X3 का एक्सटीरियर

4th जनरेशन BMW X3 को नया डिजाइन दिया गया है। इसमें आगे की तरफ होरिजेंटल और डाइगनल स्लैट्स के साथ एक बड़ी ग्रिल के साथ LED लाइट दी गई है। वहीं, दोनों साइड में LED हेडलैंप और LED डेटाइम रनिंग लाइट को शामिल किया गया है। नई BMW X3 में चौड़े व्हील्स आर्च और 4 व्हील साइज ऑप्शन भी दिया गया है। इसे पीछे से देखने पर काफी स्पोर्टी लगती है और यह है भी ऐसी। जिसमें छोटी विंडशील्ड और नई टेल लाइट्स को भी दिया गया है।

BMW X3 का इंटीरियर

नई बीएमडब्लू X3 में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ-साथ एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को भी शामिल किया गया है। इसमें AC वेंट, इंटरेक्शन बार और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इसके सेंटर कंसोल में गियर नॉब और कैमरा, वॉल्यूम, नेविगेशन और बाकी फंक्शन के लिए और भी बटन दिए गए हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील एकदम नया ही दिया गया है। इसके केबिन को पूरी तरह से रीसायकल किया गया है। इसमें अपहोल्स्ट्री और पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है।

BMW X3 का पावरट्रेन

इसमें दिए गए इंजन की बात करें तो BMW X3 में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसका पेट्रोल वाला इंजन 206 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जबकि डीजल वाला इंजन 197 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों ही इंजन को आठ-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

कीमत

नई BMW X3 के पेट्रोल वर्जन को 75,80,000 रुपये और डीजल वेरिएंट को 77,80,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मर्सिडीज-बेंज GLC, ऑडी Q5 और वोल्वो XC60 से देखने के लिए मिलेगा।

विनफ़ास्ट ने ऑटो एक्सपो 2025 में औपचारिक तौर पर की भारत में एंट्री, पेश की VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी

परिवहन विशेष न्यूज

Vinfast Unveil in Auto Expo 2025 वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Vinfast की ओर से भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर एंट्री ले ली गई है। कंपनी ने Auto Expo 2025 के दौरान अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय बाजार में पेश किया है। कंपनी की ओर से किन कारों को भारत में पेश किया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Vinfast की ओर से भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर एंट्री ले ली गई है। कंपनी की ओर से Bharat Mobility 2025 के तहत होने वाले Auto Expo 2025 के दौरान अपनी दो Electric SUVs को पेश किया गया है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। कब तक इनको लॉन्च किया जाएगा। इनके अलावा और किन कारों और बाइक्स को भारत में शोकेस किया गया है।हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

भारत आई Vinfast

वियतनाम की प्रमुख Electric Car निर्माता Vinfast की ओर से भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर अपने सफर को शुरू कर दिया गया है। कंपनी की ओर से Auto Expo 2025 के दौरान दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश किया गया है।

पेश हुई VF6

Vinfast की ओर से भारत में पहली गाड़ी के तौर पर VF6 को लाया गया है। फिलहाल इसे पेश किया गया है और जल्द ही गाड़ी को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। इसे फाइव सीटर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर लाया गया है। जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, 12.9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, Level-2 ADAS और 19 इंच अलॉय व्हील्स जैसे कई फीचर्स को दिया गया है। इसके अलावा इसमें 59.6 KWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है जिसके साथ दी गई मोटर से 201 हॉर्स पावर मिलती है। सिंगल चार्ज में एसयूवी को 381 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

भारत आई VF7

Vinfast VF7 को भी Auto Expo 2025 के दौरान पेश कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इसे भी फिलहाल पेश किया गया है और जल्द ही इसे भी भारत में लॉन्च किया जाएगा। VF7 को भी फाइव सीटर इलेक्टिक एसयूवी के तौर पर लाया गया है। इसमें भी पैनोरमिक सनरूफ, कलर्ड एचयूडी, स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स, Level-2 ADAS, 20 इंच अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स को दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें 75.3 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जाता है जिससे 431 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसमें लगी मोटर से इसे 348 हॉर्स पावर की पावर मिलती है।

शोकेस की कई कारें

Vinfast ने Auto Expo 2025 के दौरान दो कारों को पेश किया है। इसके अलावा कंपनी की ओर से कुछ और कारों को भी शोकेस किया है। इनमें VF3, VF9, VF8, VF e34 को भी शोकेस किया है। इनके साथ ही कंपनी अपने पोर्टफोलियो में VF Dragon fly नाम से इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को भी पेश करती है, जिनको Auto Expo 2025 में भी शोकेस किया गया है।

ऑटो एक्सपो 2025 में बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर और आर 1300 जीएसए लॉन्च, नए डिजाइन समेत फीचर्स से लैस

परिवहन विशेष न्यूज

BMW Motorrad ने भारत में S 1000 RR और R 1300 GSA को Auto Expo 2025 में लॉन्च (BMW S 1000 RR and R 1300 GSA Launched) कर दिया है। S 1000 RR की कीमत 2110000 रुपये और R 1300 GSA की कीमत 2295000 रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। दोनों ही बाइक को कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया गया है।

नई दिल्ली। Bharat Mobility Expo 2025 में BMW ने दो शानदार बाइक लॉन्च किया है। जिसमें से एक BMW R 1300 GS Adventure और BMW S 1000 RR है। R 1300 GSA इस ब्रैंड की सबसे बेहतरीन एडवेंचर बाइक है और S 1000 RR कंपनी की फ्लैगशिप सुपरस्पोर्ट 1000cc बाइक है। आइए जानते हैं कि BMW की इन दोनों मोटरसाइकिल को किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है।

BMW R 1300 GS Adventure

यह BMW की एडवेंचर बाइक है। इसे कंपनी भारत में 22,95,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। इसका डिजाइन अनोखा और बॉक्सी दिया गया है, जिसकी वजह से यह BMW R 1300 GS से काफी अलग दिखाई देती है।

इंजन

BMW R 1300 GS Adventure मोटरसाइकिल में 1300cc का लिक्विड-कूल्ड बॉक्सर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 145PS की पावर और 149Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

फीचर्स

बाइख में सस्पेंशन में आगे की तरफ एक जटिल टेलीलेवर सेटअप और पीछे की तरफ एक पैरालेवर सेटअप दिया गया है। साथ ही इसमें टेलीलेवर हार्ड ब्रेकिंग दी गई है, जो ब्रेकिंग दौरान फोर्क डाइव को कम करता है, जिसकी वजह से पारंपरिक सस्पेंशन सेटअप की तुलना में ज्यादा स्थिरिता मिलती है। इसके अलावा, बाइक में राइडर एडजस्टेबल राइड हाइट सस्पेंशन का ऑप्शन भी दिया गया है।

बाइक में ऑल-एलईडी लाइटिंग, 10.25-इंच टीएफटी इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और चार राइडिंग मोड्स इको, रेन, रोड और एंड्यूरो दिए गए हैं। साथ ही, इसे ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, हीटेड ग्रिप्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) के साथ-साथ कीलेस ऑपरेशन के लिए की फ़ॉब से लैस किया गया है।

2025 BMW S 1000 RR

BMW R 1300 GS Adventure के साथ ही S 1000 RR को भी लॉन्च किया गया। यह BMW की एक हाई-परफॉरमेंस सुपरस्पोर्ट बाइक है। इसमें विंगलेट्स दिए गए हैं, जो इसके स्पोर्टी लुक और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। भारत में 2025 BMW S 1000 RR को 21.10 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है।

इंजन

2025 BMW S 1000 RR में 999cc इनलाइन-फोर इंजन का इस्तेमाल किया गया है,

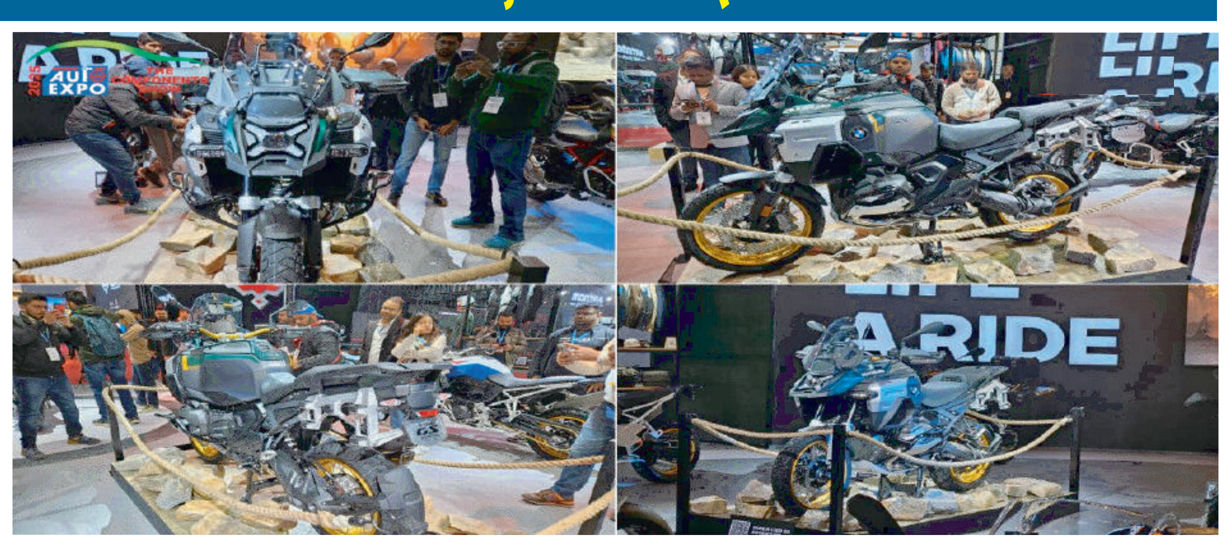

जो 208PS की पावर और 112.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक के इंजन को स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और मानक के रूप में द्वि-दिशात्मक क्विकशिफ्टर के साथ जोड़ा गया है। इसके अंडरपिनिंग में 45 मिमी इनवर्टेड फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप के साथ-साथ आगे की तरफ दोहरी 320 मिमी डिस्क और पीछे की तरफ 220 डिस्क ब्रेक दिया गया है। जिसकी वजह से बाइक रोकने में काफी आसानी रहती है।

फीचर्स

इसके फीचर्स की बात करें तो, मोटरसाइकिल को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 6.5-इंच कलर TFT और ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, कॉर्नरिंग ABS, क्रूज़ कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, ब्रेक स्लाइड असिस्ट और व्हीली कंट्रोल समेत कई हाई इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस किया गया है।

तरक्की के बरक्स पोषण की चुनौती

विजय गर्ग

रपट में कहा गया है भारत में गरीबी और पोषण से संबंधित विभिन्न अध्ययन रपटों में यह तथ्य रेखांकित हो रहा है कि गरीबी में लगातार कमी आ रही है, लेकिन लोगों के भोजन में पोषक तत्त्वों की कमी चुनौती बनी हुई है। 'स्टेट बैंक आफ इंडिया रिसर्च' द्वारा गरीबी पर जारी गरीबों को सीधे लाभान्वित करने वाले सरकारी सहायता कार्यक्रमों के कारण गरीबी में कमी आई है। वहीं विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (सोफी) रपट 2023 में कहा गया है कि भारत में पोषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। वर्ष 2020 और 2022 के बीच 7.4 करोड़ लोग अल्पपोषण के शिकार थे। इस रपट का विश्लेषण दर्शाता है कि रोजाना दो बार भोजन की परिभाषा के अनुसार भारत में भूख की समस्या तुलनात्मक रूप से कम हुई है। यानी आबादी के बड़े हिस्से की अनाज संबंधी जरूरतें मोटे तौर पर पूरी पूरी हो रही हैं। मगर पोषक की कमी बनी हुई है। इसी प्रकार वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 125 देशों के बीच भारत को 111वां स्थान दिया गया है।

एसबीआइ रिसर्च की रपट में कहा गया है कि गरीबी में कमी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से हुई है। जहां वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7 फीसद और शहरी गरीबी 13.7 फीसद थी, वहीं वर्ष 2023-24 में ग्रामीण गरीबी घट कर 4.86 फीसद और शहरी गरीबी घट कर 4.09 फीसद पर आ गई। इस रपट के मुताबिक पिछले 14 वर्ष में आमदनी बढ़ने से, जहां शहरों में हर माह प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता खर्च (एमपीसीई) 3.5 गुना हो गया, वहीं यह ग्रामीण इलाकों करीब चार चार गुना हो गया है। वर्ष 2009-10 2023-24 के बीच शहरी इलाकों में उपभोक्ता खर्च 1984 रुपए से बढ़ कर 6996 रुपए और ग्रामीण इलाकों में यह 1054 रुपए से बढ़ कर 4122 रुपए हो गया। ऐसे में शहरों की तुलना में गांवों में यह खर्च ज्यादा है।

गौरतलब है कि बीती चार जनवरी को प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए कहा था देश में ग्रामीण गरीबी तेजी से कमी आ रही है। यह पिछले वर्ष 2024 में घट कर पांच फीसद से भी कम रह गई है। साथ ही ग्रामीणों की आमदनी और क्रयशक्ति बढ़ी है। गांवों के लाखों घरों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। लोगों को डेढ़ लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। डिजिटल तकनीक की मदद से बेहतरीन डाक्टर और अस्पताल भी गांवों से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए देश को किसानों को तीन लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। बीते दस वर्षों में कृषि ऋण साढ़े तीन गुना बढ़ गए हैं। अब पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। बीते दस वर्षों में फसलों पर दी जाने वाली सबसिडी और फसल बीमे की राशि को बढ़ाया गया है। स्वामित्व योजना जैसे अभियान चलाए गए हैं, जिनके जरिए गांवों के लोगों को संपत्ति के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, 'स्टार्टअप इंडिया' और 'स्टैंड अप इंडिया' जैसी योजनाओं के जरिए मदद की जा रही है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने उनकी गरीबी को कम करने अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज दिया जाना सुनिश्चित किया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि देश में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को व्यवस्थित

में रूप से निशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की भूमिका प्रभावी बनाई गई है। देश भर में मौजूदा पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है। वर्ष 2016 से राशन की दुकानों में पाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनों की शुरुआत से रिसाव में कमी आई है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि डिजिटल इंडिया, स्वच्छ पेयजल और आयुष्मान भारत योजना और स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना अभियानों से देश में गरीबी में कमी आ रही है। खासतौर से करीब 54 करोड़ से अधिक जनधन खातों, करीब 138 करोड़ आधार कार्ड और करीब 115 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं की शक्ति से सुगठित बेमिसाल डिजिटल ढांचा गरीबों के सशक्तीकरण में असाधारण भूमिका निभा रहा है। इसके बल पर देश गरीब लोगों के खातों में सीधे राहत राशि हस्तांतरित हो रही है। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी से लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा हो चुकी है। इन सबसे गरीबी में बड़ी कमी आई है और ग्रामीण भारत विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है।

वैश्विक रपटों में भी भारत में गरीबों के सशक्तीकरण और विकास से गरीबी में कमी आने और उत्पादकता में वृद्धि होने के विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की दुनिया में गरीबी संबंधी रपट में कहा गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या वर्ष 1990 में 43.1 करोड़ थी। यह घटते हुए 2021 में 16.74 करोड़ रह गई और वर्ष 2024 में करीब 12.9 करोड़ ही गई है। नीति आयोग की तरफ मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) 2024 के मुताबिक पिछले दस वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। दुनिया के ख्यात अर्थशास्त्री थामस पिकेटी का कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ता विकास आम आदमी की आमदनी बढ़ा रहा है और गरीबी में तेजी से घटने की प्रवृत्ति उभर रही है।

लोक कल्याणकारी योजनाओं से गरीबी और भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायता मिली है, लेकिन अभी भी बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे करीब 15 करोड़ से अधिक गरीबों को सरकार के लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2030 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए और अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि यद्यपि गरीबों के सशक्तीकरण के साथ देश में प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी भारत दुनिया के उन प्रमुख दस देशों में शामिल जहां बीते बीस वर्षों में लोगों की आय में असमान इजाफा हुआ है। देश करोड़ों गरीबों के लिए हमें ऐसी नीतियां चाहिए, जो उनके लिए पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन के वितरण, उपलब्धता तय करने और उसे किफायती रखने में मददगार हो सकें।

उम्मीद है कि सरकार वर्ष 2025 में देश से गरीबी और घटाने के लिए सशक्तीकरण योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के साथ नई योजनाओं और नए रणनीतिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ेगी। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार देश में बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे करीब पंद्रह करोड़ से अधिक लोगों को 2030 तक गरीबी से बाहर लाने के लक्ष्य पर ध्यान देगी।

सफलता का विज्ञान

सफलता का विज्ञान उन सिद्धांतों, व्यवहारों और स्थितियों की पड़ताल करता है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में योगदान करते हैं। यह मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, समाजशास्त्र और व्यावहारिक रणनीतियों को मिश्रित करता है ताकि यह समझा जा सके कि व्यक्तियों को सफल होने के लिए क्या प्रेरित करता है। यहां कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं:

1. मानसिकता

विकास मानसिकता: कैरल ड्वेक द्वारा गढ़ी गई यह मानसिकता इस बात पर जोर देती है कि क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।

लचीलापन: असफलताओं से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण है। लचीले व्यक्ति चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं।

2. लक्ष्य निर्धारण

स्मार्ट लक्ष्य: ऐसे लक्ष्य जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हों, इरादों को स्पष्ट करने और प्रगति को ट्रैक करने में मदद करते हैं।

विज़ुअलाइज़ेशन: सफलता और उसे प्राप्त करने के कदमों की कल्पना करने से प्रेरणा और फोकस बढ़ सकता है।

3. आदतें और अनुशासन

परमाणु आदतें: छोटी, सुसंगत आदतें समय के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण परिणाम देती हैं (जेम्स क्लियर)।

आत्म-अनुशासन: संतुष्टि में देरी करने की क्षमता दीर्घकालिक सफलता का एक मजबूत भविष्यवक्ता है।

4. भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईक्यू)

उच्च EQ वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने, बेहतर रिश्तों और निर्णय लेने को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।

5. अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखना

सफलता अक्सर परिवर्तन के अनुकूल ढलने, अनिश्चितता को अपनाने और लगातार नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है।

6. नेटवर्किंग और सामाजिक पूंजी

सार्थक संबंध बनाना और सामाजिक नेटवर्क का लाभ उठाना अवसरों और संसाधनों के द्वार खोल सकता है।

7. स्वास्थ्य और खुशहाली

शारीरिक स्वास्थ्य, उचित पोषण, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद ऊर्जा, फोकस और उत्पादकता में सुधार करती है।

मानसिक स्वास्थ्य प्रथाएँ, जैसे कि सचेतनता और तनाव प्रबंधन, संज्ञानात्मक कार्य और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाती हैं।

8. वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि

तंत्रिका विज्ञान: यह समझना कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, जिसमें प्रेरणा में डोपामाइन की भूमिका भी शामिल है, व्यवहार को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र: निर्णय लेने में अंतर्दृष्टि और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों पर काबू पाने से बेहतर विकल्प में योगदान मिलता है।

9. दृढ़ता और धैर्य

धैर्य पर एंजेला डकवर्थ के शोध से पता चलता है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए दृढ़ता और जुनून सफलता के महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता हैं।

10. पर्यावरण और प्रणालियाँ

विकर्षणों को कम करने और फोकस को अनुकूलित करने के लिए अपने वातावरण की संरचना करना उत्पादकता का समर्थन करता है।

सिस्टम, दिनचर्या और उपकरणों का लाभ उठाना लगातार प्रगति सुनिश्चित करता है।

व्यावहारिक उपाय

लक्ष्यों को छोटे, कार्रवाई योग्य चरणों में तोड़ें।

सकारात्मक आदतें विकसित करें और प्रगति में बाधा डालने वाली आदतों को खत्म करें।

अपने आप को सहयोगी, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से घेरें।

असफलताओं से लगातार सीखते रहें और आवश्यकतानुसार रणनीतियों को समायोजित करें।

सफलता का विज्ञान सभी के लिए एक जैसा दृष्टिकोण नहीं है। इसके लिए आत्म-जागरूकता, प्रयोग और निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

तेज़ गति वाली दुनिया में सॉफ्ट स्किल्स का कालातीत मूल्य

विजय गर्ग

ऐसी दुनिया में जो अक्सर सफलता के मार्कर के रूप में धन और दिखावे का उपयोग करती है, मानव संपर्क का असली सार - सॉफ्ट कौशल - अक्सर पीछे रह जाता है हमें अक्सर उन कारकों के आधार पर आंका जाता है जो लंबे समय में प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। धन, शारीरिक विशेषताएं, जिस स्कूल या कॉलेज में हम गए उसका नाम, आकर्षक कपड़े और भी बहुत कुछ, हमारी सफलता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड हैं। हम भूल जाते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स, यदि अधिक नहीं तो, समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में मुंबई की यात्रा के दौरान मैंने हवाई अड्डे पर चेक-इन कतार में धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। काउंटर के पीछे मौजूद युवती ने यात्री को बोर्डिंग पास दिया और उसे व्हीलचेयर लेने के लिए कुछ दूर चलने के लिए निर्देशित किया। वृद्ध महिला ने गुप्त रूप से टिप्पणी की कि व्हीलचेयर अन्य रास्ते के बजाय उसके पास आने की उम्मीद थी। काउंटर वाली लड़की अनभिज्ञ लग रही थी। बाद में शाम को, मैं होटल के एक्सप्रेस चेक-इन काउंटर पर गया। जब सज्जन मेरी औपचारिकताएं पूरी करने से पहले कुछ लेने के लिए नीचे झुके तो मैंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। एक अन्य काउंटर महिला मेरी ओर देखते हुए चली गई। चूँकि काफी समय बीत जाने के बाद भी वह व्यक्ति वापस नहीं आया, तो मैंने बगल की मेज के पीछे बैठे सज्जन की ओर देखा, जिन्होंने यह कहते हुए मेरी सहायता

करने की पेशकश की कि दूसरे काउंटर पर कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। रिसेप्शन पर मौजूद भीड़ में से किसी ने भी मेरी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई। जिस निजी कंपनी में मैंने काम किया, उसने साल-दर-साल सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में ख्याति अर्जित की। मुझे मूल्यांकन के मानदंडों के बारे में आश्चर्य हुआ, खासकर तब से जब मैंने देखा कि कई अधिकारी कंपनी छोड़ रहे हैं और काम की परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं। नियम पुस्तिका में सभी सही शब्दों को लागू करने के लिए जिम्मेदार मानव संसाधन कर्मचारी मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में विफल रहे। तीनों कंपनियां निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित नाम हैं। वे सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूलों या आतिथ्य उद्योग में सर्वश्रेष्ठ योग्यता वाले लोगों को भर्ती करते हैं। उनसे सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के विपरीत, सॉफ्ट स्किल्स को समझने की उम्मीद की जाएगी। एक निजी कंपनी में काम करते समय मैं एक प्रवर्तन एजेंसी के छापे का गवाह था और उसका शिकार भी हुआ था। अधिकारी वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के साथ कार्यालय में घुस गए। मुझ पर बेरहमी से चिल्लाकर टेलीफोन न छूने का आदेश दिया गया। मेरे हाथ से मेरा मोबाइल फोन छीन लिया गया. अधिकारी 24 घंटे से अधिक समय तक कार्यालय में रहे, इस दौरान मुझे और टीम के अन्य सदस्यों को हमारे परिवारों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी गई। हमें बिना किसी कारण के अपराधियों की तरह महसूस कराया गया। हाल ही में जब मैंने वैध हरे ट्रैफिक सिग्नल को पार कर लिया था तो एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मुझे रोक दिया था। मैं हैरान था. एक अन्य पुलिसकर्मी ने मुझसे चिढ़ते हुए मुझसे दूसरे अधिकारी के साथ बहस करने का कारण पूछा। जब मैंने इस मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो उन्होंने मुझे बेरहमी से डांटा। पुलिसकर्मी ने मुझे जाहिरा तौर पर लाल सिग्नल पार करने के लिए रोका था। सौभाग्य से, चौराहे पर कैमरे थे, जिससे मेरी बेगुनाही साबित हुई। हम अपने निजी जीवन में सॉफ्ट स्किल्स की इसी तरह की कमी का सामना करते हैं। दशकों पहले, मुझे और मेरी पत्नी को दिल्ली के एक प्रसिद्ध रेस्तरां में दोपहर के भोजन के लिए टेबल नहीं दी गई थी। हम नवविवाहित युवा जोड़े थे और शायद अपने नियमित ग्राहकों की तरह कपड़े नहीं पहनते थे। आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी माता-पिता के लिए अपनी बेटियों की शादी अजनबियों से तय करने के लिए काफी हैं, बिना यह जाने कि युवक लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करेगा या नहीं। अनगिनत हैं उदाहरण. मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया गया। आजकल के बच्चे अधिक बुद्धिमान और होशियार हैं। हमें बस उन्हें हर अगले दिन एक बेहतर इंसान बनना सिखाना है। सॉफ्ट स्किल्स का पालन किया जाएगा।

नीट युजी -2025 मुद्दों को साइड-स्टेप करना

पिछले साल के संकट को देखते हुए, प्रवेश परीक्षा को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने से इनकार करना चौंकाने वाला है, पिछले साल टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) विफलता, सुधारों की सिफारिश की गई

सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को मोचन की पेशकश की। इस तरीके से परीक्षा आयोजित करने की एनटीए की क्षमता जिससे प्रक्रिया में विश्वास पैदा हुआ, पिछले साल सवालों के घेरे में आ गई थी। प्रश्नपत्र लीक होने, मनमाने ढंग से अनुग्रह अंक देने आदि के आरोप

बढ़े हुए अंकन ने परीक्षा प्रक्रिया में हितधारकों के विश्वास को कम कर दिया, जैसा कि मुद्दों पर एनटीए की प्रतिक्रिया से हुआ।

सबसे पहले, एजेंसी ने अंकन में चिह्नित विभिन्न विसंगतियों को दूर करने की कोशिश में खुद को उलझा लिया, और जब इसमें से कुछ भी सफल नहीं हुआ, तो उसे कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा का रास्ता अपनाना पड़ा। फिर, भले ही इसने किसी भी लीक से साफ इनकार कर दिया हो, जांच एजेंसियों ने कई राज्यों तक फैले पेपर-लीक/सॉल्विंग रैकेट का पर्दाफाश किया।

इस पृष्ठभूमि में, एनटीए ने एनईईटी-यूजी को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने के लिए विशेषज्ञ पैनल की एक प्रमुख सिफारिश को दरकिनार करना चुना।

पेन-एंड-पेपर मोड को जारी रखना चौंकाने वाला है।

इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले पैनल ने प्रत्येक चरण में स्कोरिंग या रैंकिंग की सीमा और परीक्षण उद्देश्यों के साथ परीक्षण को ₹बहु-चरण₹ बनाने का आह्वान किया था। इसने पारदर्शी सामान्यीकरण के साथ, कुछ हफ्तों में, कई सत्रों में परीक्षण आयोजित करने की भी सिफारिश की। परीक्षा को ऑनलाइन स्थानांतरित करने, और इसे कई चरणों और सत्रों में विभाजित करने से, लीक की कोई भी संभावना समाप्त हो जाती और परीक्षण कम बोझिल हो जाता - 2024 संस्करण में 2.4 मिलियन अभ्यर्थी एक ही दिन में परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, सैकड़ों को प्रश्न पत्र भेजे गए। देश भर के केंद्रों में लीक की आशंका बढ़ रही है।

एनटीए ने 2025 संस्करण को ऑफ़लाइन मोड में आयोजित करने के अपने निर्णय की व्याख्या नहीं की है, सिवाय इसके कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, देश की चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास नियामक, यही चाहता था। यह देखते हुए कि कैसे इस कदम ने उम्मीदवारों के बीच बेचैनी पैदा कर दी है - लीक रैकेट फिर से सक्रिय हो रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं

वास्तविक उम्मीदवारों की संभावना - जिम्मेदारी से इस तरह का त्याग समस्याग्रस्त है। परीक्षा से पहले नए परीक्षण पैटर्न से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों के पास पर्याप्त समय नहीं है - शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया कारण - ऑनलाइन परीक्षण में बदलाव को स्थगित करने का औचित्य नहीं है। उम्मीदवारों का एक बैच, चाहे बदलाव किसी भी समय हो, पायलट पूल होगा और उसी अपरिचितता का सामना करेगा जिसके बारे में वर्तमान में आशंकाएं हैं। उम्मीदवारों की पहुँच से संबंधित प्रश्न, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, हालांकि ध्यान देने योग्य हैं और साथ ही बुनियादी ढांचे की कमी भी।

ऑनलाइन नीट-यूजी। विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की

प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑनलाइन परीक्षण केंद्र, और इन्हें स्थापित करने के लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ-साथ कर्मियों की उपलब्धता और पर्याप्तता के आकलन की आवश्यकता होगी। लेकिन ये चुनौतियाँ पार करने योग्य हैं।

जिस देश को जरूरत से कहीं अधिक डॉक्टरों की जरूरत है, वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पवित्रता पर आंच नहीं आने दे सकता। एनटीए को जहां राधाकृष्णन पैनल की सिफारिशों को तत्काल लागू करने की जरूरत है, वहीं जरूरत देश में मेडिकल सीटों के पूल का विस्तार करने की भी है।

-विजय गर्ग

परीक्षा के दिनों में इन बातों का ध्यान रखिए

विजय गर्ग

परीक्षा के दिनों में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें ताकि आप तनावमुक्त रह सकें और अच्छा प्रदर्शन कर सकें:

तैयारी से जुड़ी बातें

पढ़ाई का प्लान बनाएं: समय का सही प्रबंधन करें और एक व्यवस्थित योजना पर काम करें।

महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दें: अधिक अंक वाले विषयों और कमजोर क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दें।

नियमित पुनरावृति करें: नोट्स, चार्ट और फ्लैशकार्ड का उपयोग करें।

मॉक टेस्ट दें: परीक्षा जैसे माहौल में अभ्यास करें।

स्वास्थ्य और दिनचर्या

अच्छा खाना खाएं: हल्का, पौष्टिक और मस्तिष्क को ऊर्जा देने वाला भोजन करें।

पर्याप्त पानी पिएं: खुद को हाइड्रेटेड रखें।

पूरी नींद लें: हर रात 7-8 घंटे की नींद लें।

योग और व्यायाम करें: तनाव कम करने और ध्यान केंद्रित रखने के लिए हल्का व्यायाम या प्राणायाम करें।

परीक्षा के समय

प्रश्न ध्यान से पढ़ें: पहले प्रश्न को ठीक से समझें, फिर उत्तर दें।

समय का ध्यान रखें: हर प्रश्न के लिए समय निर्धारित करें और उससे ज्यादा समय न लें।

घबराहट न करें: अगर कोई प्रश्न कठिन लगे, तो उसे छोड़कर बाद में हल करें।

उत्तर की जांच करें: अगर समय मिले तो उत्तर को दोबारा पढ़ें।

मानसिक स्वास्थ्य

सकारात्मक सोचें: अपनी मेहनत पर विश्वास रखें।

दूसरों से तुलना न करें: अपनी तैयारी पर ध्यान दें।

छोटे ब्रेक लें: पढ़ाई के बीच में थोड़े-थोड़े समय पर आराम करें।

मनोबल बनाए रखें: खुद को प्रेरित करने के लिए अपने लक्ष्य याद करें।

कांग्रेस-आप सत्ता संघर्ष के मायने

ऐसे में कांग्रेस कोई भी ऐसा दाव नहीं खेलना चाहती, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उसका नुकसान हो और बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक कांग्रेस विरोधी हो जाए

देशहित के नाम पर सत्ता संघर्ष में लगे इंडिया गठबंधन में अब रस्मी अदायगी मात्र बची है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की रही-सही कसर भी पूरी कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी न सिर्फ एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रही हैं, बल्कि सत्ता की इस दौड़ में दोनों दलों के नेता एक-दूसरे की छिछालेदार करने में भी पीछे नहीं हैं। दिल्ली के सीलमपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रणनीति को बीजेपी जैसा बताया। क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका था जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर वार किए। पिछले कई दिनों से दोनों ही राजनीतिक दल एक-दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और आप आपस में ही जब विरोधी की भूमिका निभा रही हैं, ऐसे में भाजपा को दोनों के खिलाफ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। भाजपा दोनों ही दलों की चुटकियां लेकर गठबंधन की खिल्ली उड़ाने में लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जी आए और कहा कि दिल्ली साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण है। लोग बीमार रहते हैं। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे मोदी जी झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वैसे ही झूठे वादे केजरीवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं, तो नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता।

ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को भागीदारी नहीं मिले। राहुल गांधी के बयान पर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें गाली दी। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी पर एक लाइन बोली, लेकिन जवाब बीजेपी वालों की ओर से आ रहा है। करीब सात महीने पहले ही दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव एक ही गठबंधन में रहकर लड़ी थीं, हालांकि उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव दोनों अलग-अलग लड़े, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ऐसे जुबानी हमले पहले सुनाई नहीं पड़े थे। केजरीवाल ने कहा कि क्या बात है 'मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस की देश से सत्ता समटेने में जो भूमिका भाजपा ने निभाई है, उसमें आप पार्टी का योगदान भी कम नहीं है। हाल ही में हुए कुछ राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आप को एहसास हो गया कि किसी भी तरह का गठबंधन करने से उसे नुकसान ही होगा। दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत ताकत रही कांग्रेस पार्टी पिछले दो विधानसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। वर्ष 2013 में नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने लगातार पंद्रह साल दिल्ली पर राज किया। कांग्रेस भरसक कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह सत्ता वापस मिल जाए, हालांकि आप और भाजपा की दमदार मौजूदगी में इसकी संभावना कम नजर आती है। कांग्रेस दिल्ली में अपने शीर्ष पर थी, तब उसके पास 40 फीसदी तक का वोट शेयर था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 4.26 प्रतिशत ही वोट हासिल कर सकी। इससे पहले साल 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 9.7 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। कांग्रेस 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से वजूद में आई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राजनीतिक ताकत खत्म कर सत्ता तक पहुंची है। आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की योजनाओं ने गरीब और मध्यमवर्ग के मतदाताओं को आकर्षित किया।

इस वोटर वर्ग के छिटकने से कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में और भी अलग-थलग पड़ गई। भाजपा भी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की भरसक कोशिश में लगी हुई है। इसके बावजूद कांग्रेस और भाजपा को आप के खिलाफ विधानसभा चुनावों में सफलता नहीं मिल सकी। दरअसल सत्ता की जो लड़ाई कांग्रेस दिल्ली में भाजपा से लड़ रही है, वही दूसरे राज्यों में दूसरे दलों से लड़ती रही है। यही वजह रही कि इंडिया गठबंधन तिनके की तरह बिखरता रहा है। लोकसभा चुनाव और बाद में हुए राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को जो सफलता मिली भी तो गठबंधन के घटक दलों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे में घटक दल भी कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दलों ने कांग्रेस से चुनावी गठबंधन के प्रयास किए, किन्तु एकता की रस्सी सिरे नहीं चढ़ पाई। इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आने के बाद से अस्तित्व बचाने की लड़ाई से जूझ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने आप को समर्थन दिया है। यह कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है कि गठबंधन के दल ही उसके खिलाफ हो जाएं। इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ लोकसभा चुनाव लडने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं और एक-दूसरे पर आक्रामक हैं। दिल्ली में चुनाव अभियान के तेज होते ही कांग्रेस पार्टी अचानक आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई है। पार्टी के जमीनी नेताओं से लेकर बड़े नेता तक, सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस को चुनावों के दौरान इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ इसी तरह के आरोप-प्रत्यारोपों का सामना करना पड़ा है। उस दौरान भी भाजपा इस गठबंधन पर हमलावर रही है। इतना ही नहीं भाजपा के खिलाफ कई मुद्दों पर गठबंधन के घटक दलों ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी।

क्या ग्रामीण भारत की विकास गाथा का लाभ उठाने का यह सही समय है?

पिछले दो दशकों में ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय 9% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है जबकि शहरी क्षेत्रों की वृद्धि दर 7.6% रही है। पिछले दो दशकों में ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय 9% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता के कारण ग्रामीण भारत निवेश के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बन गया है।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024 तक, ग्रामीण भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,058 डॉलर तक पहुंच गई, जो एक बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि शहरी भारत ने वित्त वर्ष 2012 में हासिल की थी। यह आंकड़ा बताता है कि ग्रामीण भारत का आर्थिक विस्तार हो रहा है, जिसका भारत की GDP पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

पिछले दो दशकों में, ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय 9% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है, जबकि शहरी क्षेत्रों की वृद्धि दर 7.6% रही है। इस बदलाव को दर्शाते हुए, खाद्य पदार्थों पर ग्रामीण खर्च, जो 1990 में कुल मासिक खपत का 59% था, वित्त वर्ष 2023 में घटकर 46.4% रह गया है। यह गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च के क्रमिक विविधीकरण (gradual diversification) को दर्शाता है।

ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति के पीछे सरकारी पहलकदमियां हैं, जो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) जैसे कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करते हैं।

इससे सड़कों के माध्यम से देश के गांवों को जोड़ा जा रहा है। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी हस्तांतरण संभव हो रहा है, जिससे बचत बढ़ रही है और महंगे अनौपचारिक लोन पर निर्भरता कम हो रही है। इन प्रयासों के तहत, राज्य सरकारों ने सामूहिक रूप से ₹3.1 ट्रिलियन सालाना (भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.1%) मूल्य के वेलफेयर और सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किए हैं।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, साइक्लिकल डिमांड में सुधार, और बाहरी चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता के कारण ग्रामीण भारत निवेश के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बन गया है। वर्षों के ठहराव के बाद, ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि ने इसे और गति दी है। जलाशयों में पर्याप्त जल स्तर, सरकारी रोजगार योजनाओं से बढ़ती श्रम मांग, और गैर-कृषि क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी से मजदूरी में सकारात्मक वृद्धि हो रही है।

हाल ही में, अग्रणी कंज्यूमर स्टेपल कंपनियों के बयानों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को बल मिला है। ये कंपनियां ग्रामीण बाजारों में मजबूत मांग की उम्मीद कर रही हैं। ग्रामीण भारत में हो रहा परिवर्तन न केवल क्षेत्रीय विकास को दर्शाता है, बल्कि एक व्यापक आर्थिक बदलाव को भी दिखाता है, जो उपभोग पैटर्न, निवेश के अवसरों, और देश के विकास की दिशा को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

Accelerate Finserv प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ विपिन बहल का कहना है कि ICICI Prudential Rural Opportunities Fund एक ऐसा फंड है, जिसके माध्यम से निवेशक ग्रामीण भारत के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ICICI Prudential Mutual Fund द्वारा लॉन्च की गई यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम ग्रामीण भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाले और उससे लाभ उठाने वाले सेक्टर्स/कंपनियों पर केंद्रित है। न्यू फंड ऑफर (NFO) 9 जनवरी से 23 जनवरी, 2025 तक खुला है।

अब फ्रॉड नंबर का फट से लगेगा पता, RBI का बैंकों को निर्देश- केवल इसी नंबर से ही करें ग्राहकों को कॉल

वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने बैंकों को खास निर्देश जारी किए हैं। ग्राहकों को कॉल करने के लिए बैंकों को 1600 फोन नंबर सीरीज प्रचार के लिए 140 फोन नंबर सीरीज का उपयोग करने को कहा गया है। आरबीआइ ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को अपने ग्राहक डेटाबेस की निगरानी करने और अनुपयोगी डाटा को हटाने के लिए कहा है।

आरबीआइ ने बैंकों से कहा है कि लेनदेन के उद्देश्य से ग्राहकों को कॉल करने के लिए वे केवल '1600' फोन नंबर सीरीज का उपयोग करें। अगर बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं प्रचार उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को काल या एसएमएस करती हैं तो उन्हें '140' फोन नंबर सीरीज का उपयोग करना चाहिए।

वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की कोशिश

आरबीआइ का मानना है कि इससे वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। इसके अलावा, आरबीआइ ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को अपने ग्राहक डेटाबेस की निगरानी करने और अनुपयोगी डाटा को हटाने के लिए कहा है।

बैंकों को आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया

बैंकों को जारी सर्कुलर में आरबीआइ ने उचित सत्यापन के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर को अपडेट करने और निरस्त मोबाइल नंबरों से जुड़े खातों की निगरानी बढ़ाने को कहा है, जिससे लिंक किए गए खातों को धोखाधड़ी में शामिल होने से रोका जा सके।

31 मार्च से पहले मानने होंगे निर्देश

आरबीआइ ने 31 मार्च 2025 से पहले निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है। आरबीआइ ने कहा है कि डिजिटल लेनदेन के प्रसार ने ग्राहकों को सुविधा प्रदान की है, लेकिन इससे धोखाधड़ी में भी वृद्धि हुई है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

एक अन्य सर्कुलर में आरबीआइ ने सभी बैंकों से कहा कि वे सभी मौजूदा और नए खातों व लाकर में नामिनी सुनिश्चित करें। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बड़ी संख्या में खातों में कोई नामिनी नहीं है। नामिनी सुविधा का उद्देश्य खाताधारक की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना तथा दावों का शीघ्र निपटान करना है।

आरबीआइ ने कहा कि ग्राहकों को नामांकन सुविधा का लाभ उठाने देने के लिए बैंक खाता खोलने वाले फार्म में उपयुक्त संशोधन कर सकते हैं। बैंक खातों में नामिनी सुनिश्चित करने के लिए बैंक और एनबीएफसी अभियान भी शुरू करें।

जनगणना के लिए सरकार ने कसी कमर, बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा, 6 साल बाद अब दोगुनी राशि की जरूरत

नई दिल्ली। 2021 की स्थगित जनगणना को कराने की प्रक्रिया की शुरुआत 2025 से हो सकती है। इसके लिए आगामी बजट में विशेष आवंटन किया जा सकता है। 2021 की जनगणना के लिए 2019 में ही 8,754 करोड़ रुपये और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के लिए 3,931 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।

छह साल बाद इसके लिए लगभग दोगुनी राशि की जरूरत पड़ेगी। जनगणना पूरी करने के लिए 33 लाख से अधिक जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षित करने और उनके लिए डिजिटल उपकरण खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वे जनगणना के आंकड़े को डिजिटल रूप में एकत्रित कर सकें।

पहले कोरोना, फिर चुनाव के कारण नहीं हो पाई थी जनगणना

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पहले कोरोना और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनगणना स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन सरकार ने इसे अब कराने का फैसला कर लिया है। आगामी बजट में इसके लिए धन के आंवटन के साथ इसकी शुरूआत मानी जा सकती है।

33 लाख कर्मियों को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग

33 लाख जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षत करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सितंबर या अक्टूबर के महीने में शुरू हो सकता है। इसके बाद राज्य और फिर जिले स्तर पर जनगणनाकर्मियों का प्रशिक्षण मार्च 2026 के पहले पूरा कर लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एक अप्रैल 2026 से घरों, मवेशियों, गाड़ियों व अन्य साजो-सामान की गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 30 सितंबर 2026 तक चलेगी।

अपग्रेड होगा एनपीआर का डाटा

घरों की गिनती के साथ ही एनपीआर के डाटा को भी अपग्रेड किया जाएगा। एनपीआर के तहत किसी गांव या मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरह की जानकारी जुटाई जाती है। पहली बार एनपीआर 2010 में संप्रग सरकार के दौरान हुआ था, जिसे 2015 में अपडेट किया गया था। सूत्रों के अनुसार घरों की गिनती के बाद असली जनगणना सात फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें देश के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों की गिनती की जाएगी।

मार्च 2026 में होगा जनगणना अपडेट करने का काम

इस बीच पैदा हुए नवजातों की गिनती कर जनगणना का अपडेट करने का काम एक से पांच मार्च 2026 के बीच किया जाएगा। चूंकि जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी, इसीलिए एक महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट उपलब्ध हो सकती है, जिसका इस्तेमाल सरकार नई नीतियां बनाने और पुरानी नीतियों को नई जनगणना के अनुरूप दुरूस्त करने में कर सकती है।

जनगणना पोर्टल पर खुद भी दे सकेंगे जानकारी

डिजिटल जनगणना में आम लोगों को भी खुद जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी उपलब्ध कराने का विकल्प दे सकती है। जनगणना कर्मी को सिर्फ इसकी पुष्टि करने की जिम्मेदारी होगी। जनगणना के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए इस बार जियो फेंसिंग की व्यवस्था की गई है।

सेंट्रल पोर्टल में सुरक्षित रहेगा पूरा आंकड़ा

इससे जनगणना के लिए दिये गए डिजिटल उपकरण में तभी आंकड़े भरे जा सकेंगे, जब जनगणना कर्मी उस इलाके में खुद मौजूद होगा। एक बार डाटा भरने के बाद आंकड़ा एक केंद्रीय पोर्टल में सुरक्षित हो जाएगा। जाहिर है केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में जनगणना की प्रक्रिया की निगरानी भी हो सकेगी।

मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा, बजट में कॉरपोरेट टैक्स में नए निवेशकों को छूट दे सकती है सरकार

परिवहन विशेष न्यूज

मैन्यूफैक्चरिंग में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार नई यूनिट के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15-18 प्रतिशत कर सकती है। अभी घरेलू कारपोरेट के लिए यह दर 22 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में मैन्यूफैक्चरिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। मैन्यूफैक्चरिंग के प्रदर्शन को बेहतर किए बगैर रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी संभव नहीं है।

नई दिल्ली। आगामी बजट में सरकार मैन्यूफैक्चरिंग व मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में नए निवेशकों को राहत दे सकती है। ताकि निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक मैन्यूफैक्चरिंग में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार नई यूनिट के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15-18 प्रतिशत कर सकती है। अभी घरेलू कारपोरेट के लिए यह दर 22 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में मैन्यूफैक्चरिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी संभव नहीं

मैन्यूफैक्चरिंग के प्रदर्शन को बेहतर किए बगैर रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी संभव नहीं है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने खुद ही विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो पिछले चार वित्त वर्ष में सबसे कम होगा। इसे देखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती विकास दर को सात प्रतिशत से ऊपर ले जाने की होगी।

विभिन्न औद्योगिक संगठनों की तरफ से वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व बैठक में कारपोरेट टैक्स में छूट देने की मांग रखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब नए निवेश पर छूट देने का मन बना रही है।

निवेश पर कॉरपोरेट टैक्स को 15 प्रतिशत

इस प्रकार की स्कीम वर्ष 2019 में भी लाई गई थी और तब नए निवेश पर कॉरपोरेट टैक्स को 15 प्रतिशत कर दिया गया था। लेकिन उसके ठीक बाद कोरोना महामारी के आ जने से इस स्कीम का बहुत लाभ नहीं मिल सका।

हालांकि मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने लिए वर्ष 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई और अब तक 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम लाई जा चुकी है। लेदर जैसे रोजगारपरक सेक्टर के लिए भी बजट में पीएलआई की घोषणा हो सकती है।

सरकार किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा बढ़ा सकती है

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आगामी एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की राशि सीमा को तीन लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका लाभ किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले 7.4 करोड़ किसानों को मिल सकता है। कृषि की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की तरफ से यह मांग पहले से की जा रही है।

क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्व और कैसे निवेश के अवसर पैदा होंगे?

कृषि क्षेत्र पारंपरिक होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के लिए पूरक बन रहा है क्योंकि आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो रही हैं जिससे स्थानीय आबादी को कमाई के अवसर मिल रहे हैं। बढ़ती आय और बेहतर जीवन स्तर के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खपत बढ़ रही है और व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हो रही है।

नई दिल्ली। भारत के आर्थिक ढांचे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की केंद्रीय भूमिका है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है, जबकि 43% आबादी को रोजगार प्रदान करती है। यहां के लोग कृषि, विनिर्माण और सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के समग्र आर्थिक प्रदर्शन में अद्वितीय योगदान देती है।

दरअसल, कृषि क्षेत्र पारंपरिक होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के लिए पूरक बन रहा है, क्योंकि आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो रही हैं, जिससे स्थानीय आबादी को कमाई के अवसर मिल रहे हैं। इसके बदले में सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश करना अब कई कारणों से सही समय पर अवसर प्रदान कर रहा है।

सबसे पहले, सरकार का ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित है, जिसमें बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से पर्याप्त निवेश किया गया है। उदाहरण के लिए, सौभाग्य योजना के तहत 2.9 करोड़ ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाई गई है, वित्त वर्ष 2023 में 6.5 करोड़ घरों को MGNREGA की सुविधा दी गई, और PMUY के तहत 11 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। ऐसे कदमों से उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे GDP की वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, बढ़ती आय और बेहतर जीवन स्तर के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खपत बढ़ रही है और व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हो रही है। इन उपायों ने सतत आर्थिक विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है।

इसके अलावा, डेटा यह दिखाता है कि गैर-कृषि नौकरियों में वृद्धि हो रही है। 1993 में ग्रामीण आबादी के लिए गैर-कृषि रोजगार का हिस्सा 22% था, जो अब बढ़कर 40% हो गया है। 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलकदमियों के तहत मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सक्रिय किया जा सकता है। बेहतर सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं और तेजी से बढ़ते डिजिटल इकोसिस्टम से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने का यह उपयुक्त समय है।

म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नितिन मित्रा का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में निवेश करने से न केवल अच्छा रिटर्न मिलेगा, बल्कि देश के संतुलित आर्थिक विकास में भी योगदान होगा। इसी दिशा में ICICI Prudential Mutual Fund ने एक नई पेशकश शुरू की है - ICICI Prudential Rural Opportunities Fund। यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम ग्रामीण भारत के विकास को आगे बढ़ाने और उससे लाभ उठाने वाले सेक्टर्स/कंपनियों पर केंद्रित है। न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 9 जनवरी से 23 जनवरी, 2025 तक खुला है।

वेतन आयोग कैसे तय करता है सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला, किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?

पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई मीटिंग में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई। यह वेतन आयोग साल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में होता है। पिछले वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। आइए जानते हैं कि वेतन आयोग सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला कैसे तय करता है।

नई दिल्ली। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और उसी के हिसाब वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। यह वेतन आयोग साल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई कैबिनेट की मीटिंग दी। आइए जानते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है, इसका गठन कैसे होता है और किन केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है।

वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग असल में एक हाई लेवल कमेटी है। इसका गठन केंद्र सरकार करती है। सबसे हालिया वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। वेतन आयोग का मकसद यह तय करना है कि आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों को सम्मान से जीने लायक उचित वेतन मिले। यह सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की सिफारिश करता है। इसमें कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों शामिल होते हैं।

वेतन आयोग का गठन कैसे होता है?

वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार किया जाता है। हालांकि, यह जरूरी बंदिश नहीं है। सरकार आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर इसका गठन 10 साल से पहले या बाद में भी कर सकती है। वेतन का गठन जरूरत के मुताबिक किसी भी सरकार के कार्यकाल में किाय जा सकता है। इसका प्रमुख कोई न्यायाधीश अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है। इसके अन्य सदस्य वेतन, वित्त, अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं।

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

7वें वेतन आयोग के मुताबिक, सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले वे सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं, जिन्हें देश के कंसॉलिडेटेड फंड से वेतन मिलता है। वहीं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs) और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। कुछ विशेष कर्मचारी, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी वेतन आयोग के दायरे से बाहर रहते हैं। इनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत तय होते हैं।

वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है। इनमें महंगाई और देश की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा फोकस रहता है।

महंगाई दर: वेतन आयोग महंगाई दर पर अधिक गौर करता है कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है और उसका कर्मचारियों की जीवनशैली पर क्या पड़ा है। वह उसी हिसाब से अपनी सिफारिश देता है।

इकोनॉमी की स्थिति: सरकार की देश की वित्तीय स्थिति पर भी विचार करता है। अगर इकोनॉमी अच्छी हालत में है, तो वेतन में ज्यादा अच्छी वृद्धि होने की गुंजाइश रहती है।

कर्मचारियों की परफॉर्मेंस: वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाजी प्रदर्शन को भी ध्यान में रखता है। अगर उनकी काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी बढ़ी होती है, तो उसका असर वेतन आयोग की सिफारिशों पर दिखता है।

बाजार के वेतन: वेतन आयोग यह भी देखता है कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी कितना बढ़ा रही हैं। इससे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन तय करने में आसानी होती है।

वेतन आयोग किस तरह की सिफारिशें करता है?

कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में वृद्धि

पेंशन योजना में सुधार

भत्तों (किफायती आवास, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ते आदि) में वृद्धि

कामकाजी परिस्थितियों में सुधार

नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया और वेतन संरचना में सुधार

कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें

मौत मिली पर बकाया नहीं , विदेश भागी फर्स्ट फ्लाईट कोरियर के खिलाफ एच एम के पी ने फिर लिखा पीएम को पत्र

– न्याय के लिए भटक रहे अहमदाबाद ,बेंगलुरु, चेन्नई ,कोयंबटूर , गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, पुणे ,जमशेदपुर, जयपुर,इंदौर, लखनऊ ,दिल्ली, नोएडा, लुधियाना,चंडीगढ़,गुड़गांव आदि के सैकड़ों कर्मचारी

सुनील बाजपेई

कानपुर। फर्स्ट फ्लाइट कोरियर प्रबंधकों द्वारा योजना बद्ध तरीके से करोड़ों की संपत्ति बेचने के बाद विदेश भाग जाने से अहमदाबाद ,बेंगलुरु, चेन्नई ,कोयंबटूर , गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, पुणे ,जमशेदपुर, जयपुर इंदौर , लखनऊ ,दिल्ली, नोएडा,लुधियाना, चंडीगढ़ और गुड़गांव आदि के सैकड़ों कर्मचारी भुखमरी से जूझने के लिए मजबूर हैं। यही नहीं न्याय का इंतजार करते-करते अब तक दर्जनों कर्मचारी मौत का भी शिकार हो चुके हैं। जबकि उनके आश्रित भी हाल-बेहाल होकर दर-दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। अब शेष बचे कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए हिंद मजदूर किसान पंचायत लगातार कमर कसे हुए है। उसने भेजे जा चुके दर्जनों के क्रम में एक और पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें कर्मचारियों की पीड़ा से अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की मांग की गई है।

विदेश भाग चुकी फर्स्ट फ्लाइट कोरियर कंपनी कंपनी के खिलाफ कई मामले न्यायालय में भी विचाराधीन हैं लेकिन विदेश भाग जाने की वजह से फर्स्ट फ्लाइट कोरियर प्रबंधकों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई भी प्रभावहीन साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार हुए इन सैकड़ों कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए हिंद मजदूर किसान पंचायत भी लगातार संघर्ष कर रही है।

कर्मचारियों के हित में न्याय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में मजदूर हितों के संघर्ष में अग्रणी हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेश मणि पाण्डेय ने बताया कि इस कोरियर कंपनी के खिलाफ 2022 से लगातार प्रार्थना पत्र भी दिए जा रहे हैं लेकिन उन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेश मणि पाण्डेय ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी बताया है कि फर्स्ट फ्लाइट कोरियर कंपनी के मालिकान तुषार ओम प्रकाश साबू और अन्य निदेशक शर्मीला ओम प्रकाश साबो, राज कुमार साबू , भरत जमनादास , हिम्मत सिंह लगड़ और सुप्रिया राजकुमार अग्रवाल आदि पीड़ित कर्मचारियों की समस्त देनदारियों को लेकर भारत की चल अचल सम्पत्तियों को बेचते हुए या फिर फ्रैनचाईजी में इस्तेमाल करते हुए विदेश भाग गये हैं ,जहां उनका कार्यालय व कार्य भी चल रहा है।

फर्स्ट फ्लाईट के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में वाद भी चलने लेकिन समुचित पते के अभाव में किसी भी तामिली की पुष्टि नहीं हो पाने की भी जानकारी देते हुए श्रमिक नेता राकेश मणि पाण्डेय ने लिखे पत्र में प्रधानमंत्री को यह भी अवगत कराया है कि जब आपके लिखे पत्रों को केन्द्रीय श्रमायुक्त को स्थानान्तरित किया जाता हैं ,तब वहां से सेवायोजकों के वर्तमान वास्तविक पते की मांग की जाती है। जबकि कम्पनी के निदेशकों द्वारा भाग जाने पर उन्हें भारत लाने और देश-विदेश की चल अचल सम्पत्तियों को जब्त कर 15 हजार करोड़ से अधिक की देनदारियों को वसूल कर उन्हें पीड़ित कर्मचारियों को देने की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की ही होती है।

लेकिन उसके बाद भी सरकार इस पर कठोरता से कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है ,जिसके फल स्वरुप न्याय का इंतजार करते-करते अबतक सैकड़ों कर्मचारी काल कलवित भी हो चुके हैं और उनके आश्रित बेसहारा होकर दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं।

कई मजदूर आंदोलनों की सफल अगुवाई कर चुके चर्चित श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय ने बताया कि लिखे पत्र में प्रधानमंत्री को आगे यह भी अवगत कराया है कि वर्ष 2022 से लेकर अब तक सैकड़ो पत्र ई-मेल आपके यानी पीएमओ के साथ-साथ सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किये गये हैं। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय ने फर्स्ट फ्लाइट कोरियर कंपनी के बंद होने से संबंधित कोई भी आधिकारिक पत्र आज तक जारी नहीं किए जाने की भी जानकारी देते हुए बताया कि फ्रैन्चाइजी के आधार पर दूसरों को अधिकृत करते हुए 15 अन्य कम्पनियों के माध्यम से पारिवारिक सदस्यों शर्मीला ओम प्रकाश साबो, राज कुमार साबू , भरत जमनादास ठक्कर , हिम्मत सिंह लगड़ और सुप्रिया राजकुमार अग्रवाल आदि को निदेशक दिखा कर फस्ट फ्लाइट के आय को उसमें स्थानान्तरित भी कर लिया गया है। जिसके खिलाफ न्याय मिलने तक हिन्द मजदूर किसान पंचायत कर्मचारियों की हित में अपना आंदोलन लगातार जारी रखेगी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा तीन जिला छोड़ सभी जिला कमेटी को किया भंग

पार्टी महाधिवेशन पूर्व बड़ी कार्रवाई

सरायकेला में डॉ0 शुभेन्दु महतो तथा प0 सिंहभूम में सोनाराम बने जिला संयोजक

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

सरायकेला। विगत एक- दो वर्षों से झारखंड की राजनीति को लेकर सुर्खियों रही सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा की दलगत राजनीति ने अब अपना केंद्रीय अधिवेशन के ठीक पहले बड़ा संगठानिक निर्णय लेते हुए पार्टी ने तीन जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिला कमेटियों को भंग कर दिया है ।उनकी जगह प्रत्येक जिले में संयोजक मंडली गठित किया गया है। पार्टी के केन्द्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कार्यालय आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार दुमका, धनबाद एवं हजारीबाग जिले को छोड़ कर पार्टी के सभी जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है तथा जिलों में संयोजक मंडली गठित करते हुए 18 जनवरी से 28 फरवरी तक युद्धस्तर पर पार्टी की सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सदस्यता अभियान के सफल संचालन के लिए पार्टी के केन्द्रीय समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा वरिष्ठ नेताओं से सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए पार्टी के सभी स्तर के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को शामिल करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ से उपर उठ कर पार्टी हित में सदस्यता अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही केन्द्रीय समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए अगामी 45 दिनों के अन्दर सभी पंचायत एवं वार्ड समितियों का पुनर्गठन करने का भी निर्देश दिया गया है तथा इसके बाद प्रखण्ड, नगर व महानगर समितियों के पुनर्गठन को लेकर नामों की अनुशंसा करते हुए केन्द्रीय कार्यालय को समर्पित करने के लिए कहा गया है।

सूचना प्रसारण मंत्री ने सिंहभूम में मोदी के 2047 विकसित भारत का बीज बोया

आई टी आई ,कैज कल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर ,कौशल विकास कार्यों का किया निरीक्षण

कार्तिक परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सिंहभूम , केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण (राज्य) सह संसदीय कार्य मंत्री डॉ एल मुरुगन अपने चाईबासा यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को उपायुक्त सभागार में आकांक्षा बैठक के तहत जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की।

इस समीक्षा बैठक में मंत्री के साथ चाईबासा उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा समेत विभिन्न विभागो और योजनाओं से जुड़े जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, आधारभूत संरचना, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन से जुड़े चाईबासा में चलाए जा रहे अभियानों और इनसे जुड़े आंकड़ों की समीक्षा कर अपने विचार और सुझाव साझा किए।

जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, कुपोषित बच्चों से जुड़े आंकड़ों, टीबी के इलाज और प्रबंधन, आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थिति, सड़क, बिजली, पानी, विद्यालयों की संख्या और वर्तमान स्थिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थिति, जन धन खातों की संख्या, मृदा स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े, एक जिला एक उत्पाद से जुड़े कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और अपने सुझाव दिए।

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, सबका साथ सबका विकास का प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, इसी ध्येय से ही हम विकसित भारत का 2047 तक निर्माण कर सकते हैं।

समीक्षा बैठक से पूर्व आज सुबह मा. केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ.एल.मुरुगन ने जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड में संचालित आईटीआई केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मा.मंत्री ने आईटीआई में विभिन्न ट्रेड आधारित वर्कशॉप का अवलोकन क्रम में प्रशिक्षणरत छात्र-छात्राओं से संवाद भी किया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस प्रखंड के करंजिया में स्थानीय लाभुक समिति द्वारा केज कल्चर के माध्यम से किए जा रहे हैं मछली पालन कार्य का अवलोकन कर लाभुकों संग संवाद भी किया गया।

तदोपरांत मंत्री ने चाईबासा सदर स्थित ₹पीएम श्री स्कूल₹ टाटा कॉलेज कॉलोनी, मध्य विद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान मंत्री ने साइंस लैब, कंप्यूटर लैब व संचालित क्लासरूम का अवलोकन करते हुए अध्यनरत विद्यार्थियों संग वार्तालाप भी किया।

मंत्री ने मीडिया को भी संबोधित किया और आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख पहलुओं पर हो रहे विकास और बेहतर क्रियान्वयन हे दिया।

उनके द्वारा जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्कूल में ड्रॉप आउट के दर को कम करना जरूरी है। आयुष्मान भारत योजना के लाभर्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया जाय, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाया जाय और अधिक रोजगार पैदा किया जाय। सेल्फ हेल्प ग्रुप की गतिविधियों को बेहतर बनाने और इसे 'एक जिला एक उत्पाद' से जोड़ा जाए।

महोदय ने जिले में ड्रोन दीदी योजना को और बेहतर बनाने का सुझाव दिया तथा श्रम विभाग के अधिकारियों को बाल श्रम को रोकने के लिए विशेष कैंपेन चलने का निर्देश दिया।

उन्होंने जिले में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटन के लक्ष्यों को पूरा करने और जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य को त्वरित कार्रवाई कर प्राप्त करने का भी निर्देश दिया।

मंत्री ने स्थानीय डिविजनल प्रबंधक से भी मीटिंग कर रेलवे की संदर्भित समस्याओं का निवारण करने हेतु जरूरी निर्देश दिए। उनके इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में जिले के जन प्रतिनिधि, योजनाओं के लाभार्थी और आम जन भी उनसे मिलने आए।

इसरो के नाम एक और उपलब्धि, विकास लिक्विड इंजन पुनः चालू करने में मिली सफलता

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (ISRO) ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में मिली सफलता के बाद इसरो ने प्रोपल्शन कांप्लेक्स के परीक्षण केंद्र में विकास तरल इंजन को फिर से चालू करने संबंधी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया किया। विकास इंजन पीएसएलवी पीएसएलवी रॉकेट की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा। इसको एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।

बेंगलुरु। भारत ने अंतरिक्ष में दो उपग्रहों की डॉकिंग कराकर इतिहास रचने के बाद फिर कमाल किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को कहा कि महेंद्रगिरि में प्रोपल्शन कांप्लेक्स के परीक्षण केंद्र में विकास तरल इंजन को फिर से चालू करने संबंधी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया किया।

इसरो ने क्या कहा ? विकास इंजन का उपयोग राकेटों के तरल चरणों (लिक्विड स्टेज) में किया जाता है। इसरो के बयान के अनुसार, यह परीक्षण 17 जनवरी को किया गया। यह परीक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास में मील का पत्थर है। विभिन्न परिस्थितियों में इंजन को फिर से शुरू करने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं। विकास इंजन पीएसएलवी, पीएसएलवी रॉकेट की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा।

विकास इंजन को बंद कर पुनः चालू किया गया : परीक्षण के दौरान इंजन को 60 सेकंड के लिए चालू किया गया फिर इसे 120 सेकंड के लिए बंद किया गया, फिर चालू किया गया। परीक्षण के दौरान इंजन के सभी मानक अपेक्षा के अनुरूप थे। इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में भी परीक्षण किया गया था। इसके अलावा, इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने शुक्रवार को इसरो के एलवीएम3 राकेट के 'कोर लिक्विड स्टेज' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

डॉकिंग में मिली थी सफलता : इसरो में शुक्रवार को 'स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट' (Spadex) के तहत उपग्रहों की सफल 'डॉकिंग' का एक वीडियो भी साझा किया था। इसरो ने गुरुवार को ऐतिहासिक 'डॉकिंग' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और ये करने वाला यह विश्व का चौथा देश बन गया है। इस सफलता के बाद इसरो ने एक बयान जारी किया था। एक्स पोस्ट में इसरो ने कहा था कि भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया ! इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पैडेक्स) मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल की। इस पल का साक्षी बनकर गर्व महसूस हो रहा है ! डॉकिंग के बाद एक ही अंतरिक्षयान के रूप में दो उपग्रहों का नियंत्रण सफल रहा।

दिल की राहें

--- संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल

मैं ज़िन्दगी के रास्ते में,
हर ग़म को सहता जाता,
मुस्कुराहट ओढ़े रहता,
दिल में दर्द छुपाता जाता।

तन्हाई से न हारता,
अपनी रूह को समझाता,
चाहतें थी बहुत, मगर
मैं हर ख़्वाब को भूलता जाता।

कल मंज़िल पास थी मेरे,
सपनों की एक आवाज़ थी,
चलता तो बिछड़ जाता,
रुकता तो सफ़र छूट जाता।

दुविधा थी हर कदम पे,
किसे चुनूं, किसे छोड़ूं,
दिल का रास्ता थामे हुए,
मैं खुद को ही खोजता जाता।

सिंगापुर के राष्ट्रपति ने पट्टचित्रा गांव पुरी की हरिराजपुर का दौरा किया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम इन दिनों ओडिशा के दौरे पर हैं। शनिवार को वह पट्टचित्र गांव के नाम से मशहूर रघुराजपुर पहुंचे। थर्मन गांव का दौरा कर रहे थे। उन्होंने लोगों के घरों में फिल्म के डेमो देखे और उन पर चर्चा की। उन्होंने संग्रहालय और प्रदर्शनी स्थल में पेंटिंग्स देखीं।इससे पहले, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने शुक्रवार को भुवनेश्वर स्थित हस्तशिल्प संग्रहालय आर्ट गैलरी का चार घंटे का लंबा दौरा किया और ओडिशा की कला, हथकरघा और हस्तशिल्प की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने वहां सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक समय बिताया। सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपट्टी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। राष्ट्रपति षणमुगरत्नम ने कला संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं का दौरा किया और ओडिशा की कला, हस्तशिल्प और हस्तशिल्प को देखा।

उन्होंने जगन्नाथ गैलरी में काफी समय बिताया और ओडिशा की आध्यात्मिक चेतना और परंपराओं की भी प्रशंसा की। इस अवसर पर राष्ट्रपति की पत्नी ने एक साड़ी खरीदी और उसका भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया। गौरतलब है कि भारत की यह डिजिटल भुगतान प्रणाली एक आसान और सरल भुगतान प्रणाली के रूप में दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुकी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वहां रात्रि भोज किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। राष्ट्रपति को पारंपरिक ओडिया भोजन परोसा गया। राष्ट्रपति षणमुगरत्नम ने कहा कि ओडिशा का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के लिए ओडिसी और सिंगापुर का फ्यूजन नृत्य प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रपति ने ओडिसी नृत्य और संगीत की भी प्रशंसा की।

ओड़िशा में नये शहर बनाये जायेंगे; सिंगापुर के सुरवान जुरोंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : राज्य में कई शहर बसाए जाएंगे। सिंगापुर से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। एक नया शहर बनाने के लिए सिंगापुर की सुरावन जुरोंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसे-जैसे शहर का विकास होगा, कई नई एनएसी बनाई जाएंगी और कई एनएसी को नगर पालिकाओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही निर्णय लेगी।

सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम इस समय ओडिशा के दौरे पर हैं। ओडिशा सरकार के विभिन्न विभागों और सिंगापुर के विभिन्न संगठनों के साथ 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023